RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-03, अंक - 09 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 03 दिसम्बर 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

ईश्वर हमसे सफल होने की अपेक्षा नहीं करता, वह तो बस अपेक्षा करता है कि हम प्रयास करें।

मदर टेरेसा

पांच राज्यों में कोरोना कंट्रोल के लिए भेजी गई विशेषज्ञों की टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि, देश के 5 राज्य कोरोना के सक्रिय मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं। इन राज्यों के हालात वायरस संक्रमण के बोझ को बढ़ा रहे हैं। संक्रमण में तेजी दिखा रहे शीर्ष पांच राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इकट्ठे किए गए तुलनात्मक आंकड़ों ने दिखाया है कि, 1 नवंबर के बाद से, पंजाब के सक्रिय केस में 3 हजार 855, हिमाचल प्रदेश में 54 हजार 69, मध्य प्रदेश में 5 हजार 842, हरियाणा में 6 हजार 171 और राजस्थान में 13 हजार 551 की वृद्धि देखी गई है।

वर्तमान में पंजाब में 1 लाख 38 हजार 685, हिमाचल प्रदेश में 8 हजार 918, मध्य प्रदेश में 17 हजार 705, हरियाणा में 20 हजार 200 और राजस्थान में 30 हजार 305 सक्रिय केस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने कहा, ये वे राज्य हैं जहां केंद्र ने विशेषज्ञों की टीमों को भेजा है ताकि वे राज्य सरकार को रोग प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर नियंत्रण में मदद कर सकें।

चक्रवात बुरेवी मचाने आ रहा तबाही

नईदिल्ली, एजेंसी। चक्रवात निवार के हफ्तेभर के अंदर फिर से एक और चक्रवात दस्तक देने वाला है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर चक्रवाती तूफान 'बुरेवी' का रूप ले लिया है और आज रात श्रीलंकाई तट से इसके टकराने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुरेवी चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने केरल के 4 राज्यों- तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा और अलाप्पुझा में 3 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा है कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास कोमोरिन इलाके की ओर आने की आशंका है।

माही की 200 करोड़ की योजना को लगा पलीता, एक साल भी नहीं चल पाई, धरातल से हुई गायब

माही परियोजना में हुए भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगत रहे किसान

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

धार-झाबुआ के लिए माही परियोजना किसानो के लिए जीवनदायनी है, इस कैनाल से झाबुआ जिले की हजारो बीघा जमीन जो सिंचित नही थी और उस जमीन में बरसात के पानी से एकाध फसल ले लेते थे और उसके बाद पानी का साधन नही होने की वजह से वह जमीन ऐसे ही खाली पडी रहती थी। माही डेम बनने के बाद कैनाल निकाली गई, तब से पेटलावद क्षेत्र के किसान खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी कैनाल से मिल रहा है, लेकिन जामली के किसानों को जामली और उसके आसपास के किसानो की 550 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करके उन्हे फ़सल के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था जल संसाधन विभाग को योजना के माध्यम से देना है। यह योजना जामली के किसानों को पानी देने के लिए 200 करोड की है। यह योजना 2019 से विभाग प्रारंभ करना बता रहा है और 2019 में 550 हेक्टेयर सिंचित की है, जबकि जामली के किसानो का कहना है कि, वर्ष 2019 में योजना ट्रायल के नाम से प्रारम्भ की थी और यह योजना दो-तीन बार चालु की गई और बंद कर दी।

इस प्रकार देने था पानी

माही कैनाल से लिफ्ट के माध्यम से पानी खीचकर विभाग द्वारा बनाए गए कुएं में एकत्रित करना और कुएं नं. 1 में 25-25 हॉर्स पॉवर की 2 मोटरो से खीचकर कुएं नं. 2 में 30-30 हॉर्स पॉवर के 2 मोटरो से पानी एकत्रित करना फिर कुएं नं. 1 व 2 से किसानो के लिए पांच हॉर्स पॉवर, आठ हॉर्स पॉवर की मोटरे डालकर पाईप के माध्यम से खेतो तक पानी पहुचाया जाएगा। किसानो द्वारा बताया गया कि, जो पाईपलाईन खेतो में से होकर डाली गई है। वह पाईप लाईन ज्यादा गहराई में नही बिछाई गई है, जो किसानो के खेत जोतने पर जगह-जगह से टुट गई है और ठेकेदार द्वारा बिछाई गई लाईन पूरी न बिछाते हुए आधी-अधुरी बिछाई ही गई है। जो कुएं बनाए गए है उनका निर्माण घटिया स्तर का हुआ है। कुआ नं. 1 की एक दिवार पूरी टुट कर जमीदोज हो गई और तीन दिवारे अपने घटिया निर्माण कार्य दर्शा रही है जिससे हमेशा किसी अनहोनी घटना होने का डर बना रहता है।

विद्युत कनेक्शन की हालत खराब, गिरे पोल, ट्रांसफार्मर में ऑइल तक नही

कुओ के पास ट्रांसफार्मर लगे है आज की स्थिति में उन टांसफार्मरो में लगने वाला ऑइल नही है और विद्युत लाईन अप्रेल-मार्च से कटी हुई पडी है व अस्त-व्यस्त हो गई है। कुआ नं. 2 के पास विद्युत पोल टुटा हुआ पडा है जिसके तार जमीन पर लटक रहे है। रबी फसल बोने के लिए किसान अपनी तैयारी से बैठे है और पानी की प्रतिक्षा में है लेकिन विभाग के अधिकारियो, ठेकेदार के कान में जू तक नही रेंग रही जिससे जामली के किसान बहुत ही परेशान है। किसानो ने अपनी परेशानी को लेकर कलेक्टर को लिखित में अवगत कराया कि, माही कैनाल में डेम से पानी छोड़ दिया गया है। लेकिन जामली के किसानो को योजना के बिना पानी नही मिल सकता क्योंकि योजना टुटी-फुटी पडी है। इस स्थिति में जामली की 550 हेक्टेयर जमीन किस तरह से सिंचित होगी। जामली के किसान गुलाबचंद पाटीदार, हरीराम, लीलाधर, हीरालाल, शांतिलाल, मनिराम, रन्छोड, अम्बाराम, मुकेश, नंदलाल, अम्बाराम, सरपंच राजेन्द्र, गटुलाल, अम्बाराम, अनोखीलाल, भेरूलाल, नरेशचंद दवे, बाबूलाल, भेरूलाल आदि ने बताया कि, हमें जल्द से जल्द पानी उपलब्ध नही करवाया तो हम किसान लोग धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। सरकारे किसानो कि हितैसी बनती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जैसा कि जामली के किसानो के साथ हो रहा है, प्रशासन ने हमारी समस्याएं जल्द से जल्द नही सुलझाई तो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगें, जिसकी जवाबदारी प्रशासन कि होगी।

दिल्ली को जाम करने की कवायद तेज, बैठक भी रही बेनतीजा, अब चिल्ला बॉर्डर पर डटे किसान

नई दिल्ली, एजेंसी। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन का आठवां दिन होने वाला है। जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डट गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में डटे किसानों ने प्रदर्शन किया और मंगलवार शाम से ही लोगों को जाम की परेशानी से जूझना पड़ रहा है।

सरकार से बातचीत विफल

तीन नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच मंगलवार को साढ़े तीन घंटे से अधिक देर तक चली बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए किसान समिति के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान संगठन प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। हालांकि, गतिरोध समाप्त करने को लेकर अगली बैठक आज बुलाई गई है। बैठक में आंदोलन में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विज्ञान भवन में बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि, बैठक में 30 से अधिक किसान संगठनों के 35 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बातचीत सकारात्मक रही, सरकार ने किसान संगठन के प्रतिनिधियों के सामने मुद्दे पर बातचीत के लिए एक किसान समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, इसमें चार से पांच किसान संगठन के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ व कृषि मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे, जिससे तीनों कृषि कानून के बारे में चर्चा की जा सके, लेकिन किसान संगठन के प्रतिनिधि इसके लिए तैयार नहीं हुए। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना था कि, आंदोलन में शामिल सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होनी चाहिए।

इससे पहले भी केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक के बाद किसानों के साथ चर्चा कर इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की थी। हालांकि, किसानों के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रही थी और एक बार फिर इस मुद्दे पर आज किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी।

सर्दी का सितमः मध्य प्रदेश में टूटेगा 54 साल का रिकार्ड

भोपाल, एजेंसी। राजधानी भोपाल में लगता है इस सर्दी के मौसम में पिछले 54 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार नवंबर में रात का न्यूनतम तापमान 15 से ज्यादा बार सामान्य से कम रहा है। इसी आधार पर मौसम वैज्ञानिक इस बार राजधानी भोपाल में दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जता रहा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि यही हाल रहा, तो भोपाल में इस बार पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे जा सकता है।

नए मंण्डल अध्यक्ष का दायित्व है वो काम करेगा, मैं बोलना शुरू करूगां तो तुम नरसिंगपुरा छोड़ दोगे - भाजपा जिलाध्यक्ष नायक

कार्यकर्ताओ की पार्टी कहने वाली भाजपा कार्यकर्ताओ की कर रही उपेक्षा, जिले में भाजपा की गूटबाजी अब आ रही सड़कों पर

माही की गूंज झाबुआ।

भाजपा, कार्यकर्ताओं की पार्टी है कहती है, पर जिले के शीर्ष नेता भाजपा की कथनी व करनी में अंतर को स्पष्ट कर रही है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर जिले का शीर्ष नेतृत्व अपने कुशल नेतृत्व का ढिंढोरा पिट झूठी वाहवाही के साथ अपने कुशल नेतृत्व का दावा कर रहे हैं। जिले में भाजपा की गुटबाजी अब इतनी चरम पर आ चुकी है कि, अपने आप में चरित्रवान एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी कहने वाले नेताओं की चरित्रता व गुटबाजी किस निचले स्तर पर जा चुकी है जो अब सड़कों पर आकर सार्वजनिक हो रही है।

भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश संगठन तक अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले मनोहर सेठिया जिले की राजनीतिक व गुटबाजी कि ऐसी भेंट चढ़े की उनके साथ रहे सह साथियों ने मिलकर जिले से बाहर जाकर अपने शौक-मौज अपने चरित्र को गिराकर किए, परंतु राजनीति में कहा जाता है कि, कौन कब किसका हो या कौन कब किसका विरोधी हो जाए कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा ही मनोहर सेठिया के साथ रहे व चरित्रहीन शौक-मौज भी किए और जिसके फोटोग्राफसाथ में रहेने वाले साथी कीर्ति राठौर के मोबाइल में लम्बे समय तक रखे और साथ में रहने वाले कीर्ति राठौर ने ही जिले की गुटबाजी राजनीति के साथ 6 अंको में लेन-देन कर फोटो वायरल किए गए, यह बात भाजपाई नेता ही कह रहे हैं।

फोटो वायरल होने के बाद मनोहर सेठिया का पद जिला संगठन से छोड़ना पड़ा। पद के साथ ही भाजपा के साथ समाज में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ रखने वाले सेठिया की प्रतिष्ठा को उनके ही भाजपा नेता ने धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी यह सार्वजनिक है।

वही 9 मई को प्रदेश संगठन ने जिले के संगठनात्मक शीर्ष पद पर जिलाध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण नायक को इस आशय के साथ नियुक्त किया गया कि, लक्ष्मण नायक संघ से जुड़ा होकर निर्विादित है और जिले में हो रही गुटबाजी व कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा को खत्म कर जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, पर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ। नतीजन नायक के अध्यक्ष बनने के 7 माह बीत जाने के बाद भी राजनीतिक गुटबाजी व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को खत्म करने में सफलता नहीं पा सके लेकिन यह जरूर देखा गया कि, जिला अध्यक्ष का पद मिलने के बाद स्वयं नायक में भी ऐसा अहम आ गया कि, वे भी खुलेआम कार्यकर्ताओं को विश्वास में ना लेकर उनकी उपेक्षा कर, कार्यकर्ता को उनके ही गांव से अपने पावर के साथ रवानगी करवा देने की बात कहकर कार्यकर्ता को खुले रूप से धमकाया गया।

कार्यकर्ता रखते हैं सम्मान की अपेक्षा

भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये ही कहना है कि, हमें संगठन में काम के बदले सिर्फसम्मान चाहिए, लेकिन जिला नेतृत्व सम्मान के बजाए सदैव उपेक्षा ही करते आए हैं। जिला अध्यक्ष ने जिले की गुटबाजी के साथ 6 माह 17 दिन बाद 26 नवंबर को जिले के 19 मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई। उक्त घोषणा के साथ ही राणापुर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष कीर्ति राठौर को भाजपा के ही नेताओं ने गुटबाजी के चलते ऐसा घेरा की उसके भांजे की अश्लील चरित्रता को सार्वजनिक करने में कोई कसर नही छोडी वही महिला की रिपोर्ट पर बलात्कार व ब्लैक मेलिंग का मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तारी भी हो गई। ऐसे कई गुटबाजी के मामलो के बाद भी किसी भी स्थिति में जिला नेतृत्व पार्टी की छवी को सुधारने व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना कर उन्हें विश्वास में लेकर सम्मान देने की रूपरेखा नहीं बना पा रहे है, नतीजन आज भी गुटबाजी व कार्यकर्ताओं की सरेआम उपेक्षा होने के कारण एक मंडल स्तर का भाजपा समर्पित सक्रिय कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के साथ अपनी व कार्यकर्ताओं के सम्मान कि बातकर कार्यकर्ताओं के हितों के लिए तू-तू ,मै-मै करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका उदाहरण जिले के नौगांवा मंडल के पुर्व अध्यक्ष रूपसिंह बारिया व जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिह नायक के मध्य हुई बात की ऑडियो सुनकर साफहो रहा है कि, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किस कदर से भाजपा नेता कर रहे हैं।

उक्त मामले में नौगांवा मंडल के भाजपा नेता लालचंद्र बारिया ने माही की गूंज को बताया कि, 29 नवंबर को अगराल व नरसिंगपुरा में पेयजल योजना का उद्घाटन आयोजन रखा गया, लेकिन उक्त आयोजन की जानकारी उन कर्मठ एवं कर्मनिष्ट कार्यकर्ता जो जिला भाजपा नेतृत्व के कहने पर पार्टी हित में सदेव कार्य करते हैं और क्षेत्र में भाजपा को हमेशा लीड दिलाते हैं पर उन कार्यकर्ताओं को भी उक्त आयोजन की सूचना तक नहीं दी गई, जिस पर पूर्व नौगांव मंडल अध्यक्ष रूपसिंह बारिया निवासी नरसिंगपुरा ने जिलाध्यक्ष से अनुरोध करना चाहा कि, उक्त पेयजल योजना का उद्घाटन उन सभी कार्यकर्ताओं को सूचना देकर करे जो, सदैव पार्टी हित में कार्य करने के लिए खड़े होते हैं, इसलिए 29 नवंबर का आयोजन नहीं रख तारीख बढ़ाकर कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर आयोजन करें, उक्त अनुरोध जिला अध्यक्ष श्री नायक से किया। परंतु कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए क्षेत्र में बिना सूचना के ही उक्त आयोजन को किया जा रहा था, जिसपर जिलाध्यक्ष के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष रूपसिंह बारिया की मोबाइल पर तू-तू ,मै-मै हुई और उसी तू-तू, मैं-मैं में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के साथ अपने पद के अहम व पावर में आकर जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक ने यहां तक कह दिया कि, नए मंडल अध्यक्ष का दायित्व है वही काम करेगा और मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुम अपना गांव नरसिंगपुरा छोड़ दोगे, कहकर नायक ने यह स्पष्ट कर दीया कि, जिले में पुराने कार्यकर्ता नहीं सिर्फनए मंडल अध्यक्ष ही कार्य करेंगे और जो कर्मठ कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता साथी के हक में बात करेगा उसे उसके ही गांव से जिलाध्यक्ष की दबंगई के साथ गांव निकाला करवा दिया जाएगा।

चरित्रता की बात करने वाले भाजपा नेता है चरित्रहीन

राणापुर में शीर्ष नेता के बाद से भाजपा गुटबाजी के साथ ही जिले के कुछ शीर्ष नेता की चरित्रहीनता की चर्चाएं सार्वजनिक होती रही है, जिसमें भाजपा की गुटबाजी के साथ छनकर आ रही चर्चाओं में सामने आ रहा है कि, एक अबला महिला अपने किसी कार्य को करवाने हेतु वर्तमान संगठन के एक शीर्ष नेता के पास यह अपेक्षा लेकर गई कि, वह नेता पार्टी के शीर्ष पद पर होकर चरित्रवान नेता है और वह अबला नारी का सहयोग कर उसे न्याय दिलवाएगा।

लेकिन अबला नारी शीर्ष नेता से अपने कार्य को करवाने हेतु मिली और फोन पर भी अपना कार्य करने हेतु निवेदन किया, लेकिन यह शीर्ष नेता भी छनकर आई बात अनुसार एवं गूंज को सुनाई ऑडियो अनुसार ऐसा चरित्रहीन निकला की महिला को गलत नियत से राजस्थान के एक धार्मिक स्थल पर ले जाने की बात कही एवं अनैतिक नियत से महिला को शीर्ष नेता ने तीन बात मानने व वीडियो कॉलिंग के साथ बात करने का कहने लगा। वही ऐसी बात भी अबला महिला को कहीं की जो स्पष्ट करता है कि, भाजपा का उक्त शीर्ष नेता भी कितना चरित्रहीन है। लेकिन अबला महिला चरित्रवान होने के कारण शीर्ष नेता अपने बदनियत में सफल नही हो पाया।

गूंज के सूत्र ने आश्वस्त किया कि, माही की गूंज को उक्त शीर्ष नेता के महिला के साथ हुई चरित्रहीन नियत से की गई बात का ऑडियो भी उपलब्ध करवाएगा। अगर गूंज को यह ऑडियो मिलता है तो वह जनहित के लिए आवश्यकता हुई तो सार्वजनिक भी किया जाएगा।

- कार्यकर्ता की उपेक्षा के साथ जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ता को गांव निकाला करवा देने की कही बात सुने क्यु आर कोड स्कैन कर।

10,11 और 12 दिसंबर को होगा मतदान

युकां अध्यक्ष के लिए संभागवार तीन दिन चलेगी वोटिंग, रिजल्ट एक सप्ताह बाद

प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के 2 विधायक, नेता पुत्रों सहित कुल 12 उम्मीदवार मैदान में

भोपाल

लंबे समय बाद यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सियासी माहौल गरमा गया है। सात साल तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले कुणाल चौधरी की जगह अब नया अध्यक्ष चुना जाना है। इसके लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के 2 विधायक, नेता पुत्रों सहित कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के मतदान की तिथियां घोषित हो गई हैं। 10,11 और 12 दिसंबर को ऑनलाइन मतदान होगा।

उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अपनी यूथ ब्रिगेड में जान फूंकने की तैयारी में है। यही कारण है कि लंबे समय से अटका यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने की उसने पूरी तैयारी कर ली है। 12 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। यूथ कांग्रेस के सदस्य मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे। दिसंबर के आखिरी तक नतीजों का ऐलान हो जाएगा। नये अध्यक्ष के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस को मजबूती देने की तैयारी है, ताकि 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी यूथ ब्रिगेड तैयार कर सके, लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस विधायक और नेता पुत्रों के सहारे संगठन को कितना मजबूत कर पाती है। युवा कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम प्रभारी मकसूद मिर्जा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए पहले 18 नामांकन हुए थे। दोबारा नामांकन की प्रक्रिया में दस नामांकन और आए। इसमें सांवेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रेमचंद गुड्डू के पुत्र अजीत बोरासी का नाम प्रमुख है। वहीं दो विधायक सिद्धार्थ कुशवाह और विपिन वानखेड़े मैदान में हैं।

इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव, हर्षित गुरू, मोना कौरव, वंदना बेन, पिंकी मुदगल, जावेद खान, अंकित डोली और एनएसयूआई के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी दावेदार हैं। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। एक मतदाता पांच वोट डालेगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव के लिए डालेगा। मतदान एप के माध्यम से होगा। इसमें पात्रता उसे ही मिलेगी, जो पंजीकृत है। मतदाता के पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने पर ही मतदान कर पाएंगे।

अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल चेहरे

कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी का चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है। अंकित डोली का चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट है। हर्षित गुरु का चुनाव चिन्ह बाल्टी है। जावेद खान का ब्लैक बोर्ड, मोना कौरव का किताब, पिंकी मुद्गल का मोमबत्ती, संजय यादव का पंखा, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का तीर, विधायक विपिन वानखेड़े का कॉम्पैक्ट, वंदना बेन का कंघी, विक्रांत भूरिया का नाक और विवेक त्रिपाठी का शर्ट चुनाव चिन्ह है।

पार्टी में टूट के डर से उपचुनाव में भितरघात पर बड़ी कार्रवाई से कतरा रही कांग्रेस

भोपाल

नवंबर माह में मध्यप्रदेश में संपन्न हुए 28 उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में कांग्रेस की हार हुई है। वहां चुनाव परिणाम के बाद शिकायतों का सिलसिला भी बढ़ गया है। भीतरघात के मामलों को लेकर पार्टी फोरम पर कई शिकायतें की जा रही हैं। भिंड की मेहगांव सीट को लेकर तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुशासनहीनता और भीतरघात के मामलों में कोई बड़ी कार्रवाई के मूड में नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि सख्ती करने पर पार्टी में और भी टूट-फूट हो सकती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा।28 उपचुनाव के बाद जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार हुई है। वहां से पार्टी को भीतरघात की शिकायतें मिलना शुरू हो गई है। खासकर भिंड जिले की मेहगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे की हार के बाद वहां की जिला कार्यकारिणी ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इसी तरह सागर जिले की सुरखी विधानसभा में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जैसीनगर ब्लॉक के अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बधाई देते हैं और उनके पक्ष में कई कांग्रेसी नेताओं के काम करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मंदसौर की सुवासरा विधानसभा से भी भीतरघात की शिकायतें आई थी। हालांकि इस मामले में कांग्रेस ने तीन लोगों को पार्टी से बेदखल कर दिया है।

शिकायतों को भी किया अनसुना

इस तरह की शिकायतों को लेकर कांग्रेस का रुख ज्यादा सख्त नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि जब उप चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, तब इस तरह की शिकायतें ना के बराबर सुनने को मिलीं। पार्टी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक और प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मद्देनजर मतदान के 24 घंटे पहले तक चुनाव क्षेत्र में रहे हैं और उन्होंने इस तरह की शिकायतें पार्टी से नहीं की है। पार्टी का मानना है कि चुनाव परिणाम के बाद इस तरह की शिकायतें और चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस मामले में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

आज एकजुटता पहली प्राथमिकता

उपचुनाव में भीतरघात और दूसरी शिकायतों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का रुख सख्ती वाला बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के रुख को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस इसलिए सख्ती नहीं करना चाह रही है। क्योंकि इससे पार्टी की एकजुटता पर खतरा बढ़ेगा और गुटबाजी बढ़ सकती है। पार्टी हाल ही में बड़ी बगावत का सामना कर चुकी है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी और सिंधिया खेमा लगातार कांग्रेसी नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने पर ज्यादा फोकस कर रही है ना कि सख्ती दिखाने पर।

शिकायतों पर जांच के बाद होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री राजीव सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में इस बार हमें पूरे विधानसभा चुनाव में कहीं से कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है। केवल एक दो जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं। उनको संज्ञान में लिया जाएगा और पहले यह देखा जाएगा कि किस वजह से यह बात सामने आई है। क्योंकि चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने पार्टी फोरम पर कोई बात नहीं रखी थी कि किसी ने उनका विरोध किया है। अब परिणाम आते हैं और परिणाम के बाद जब कार्यकर्ताओं के रुझान आते हैं, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं। हम उम्मीदवारों के लगातार संपर्क में थे। हर विधानसभा में हमारे पर्यवेक्षक थे और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से एक दिन पहले विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा। जिन इलाकों से शिकायतें आई हैं। उसमें काफी वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे और लगभग पूरे समय वहीं रहे हैं। कहीं से कोई बात आती है, तो प्रदेश अध्यक्ष उन से चर्चा करेंगे कि चुनाव के दौरान भी इस तरह की बात सामने आई थी या बाद में कुछ लोगों ने अलग से शिकायत दर्ज कराई है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। कहीं से कोई इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं।

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

सरकारी ऑफिस में गंदगी देख गुस्सा हुए मंत्री, खुद साफ किया शौचालय

बैतूल

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर घोड़ाडोंगरी तहसील के सारनी पहुंचे। जहां उन्होंने सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने शौचालयों में गंदगी का नजारा देखा तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। फिर खुद ही ब्रश उठाया और शौचालय की सफाई में जुट गए। मंत्री को शौचालय की सफाई करते बाकि लोग भी शौचालय की सफाई करने लगे।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कार्यालय में इतनी गंदगी क्यों है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय में साफ सफाई रखने की बात कही। साथ ही साफ सफाई में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने वर्ष 2019-20 में पावर हाउस से संबंधित सिविल संधारण के रख-रखाव की जानकारी ली। साथ ही बांध क्षेत्र से जलकुंभी की सफाई के संबंध में जानकारी ली गई।

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एश पाइप लाइन की चोरी के संबंध में भी मुख्य अभियंता से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पावर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए।गेट से आने-जाने वालों पर कार्यालयीन समय की पाबंदी सुनिश्चित की जाए।ऊर्जा मंत्री ने ठेका श्रमिकों को कम वेतन प्राप्ति संबंधी शिकायत पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।ऊर्जा मंत्री ने विद्युत गृह क्रमांक-2 में साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया। साफ-सफाई में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता राजीव श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री को सतपुड़ा पावर प्लांट की व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी।ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से विद्युत उत्पादन को लेकर चर्चा की। इसी दौरान प्लांट में अंदर प्रवेश ना देने को लेकर सुरक्षा विभाग व भाजपा कार्यकर्ता में बहस हो गई। जिस पर भाजपा नेता कमलेश सिंह ने कहा कि प्लांट में चोरी करने वाले चोरों को आसानी से प्रवेश दिया जाता है। आम लोगों को बाहर रोक देते हैं।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कुछ महीने पहले एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसमें वे ग्वालियर के मोती महल में एक शौचालय साफ करते नजर आ रहे थे। यहां पर सरकारी आफिस हैं। तोमर ने पहले शौचालय की शीट को झाडू से साफ किया, उसके बाद उन्होंने हाथ से भी उसे अच्छे से क्लीन किया। बता दें इससे पहले भी प्रद्युम्न सिंह तोमर नालियों में उतरकर साफ-सफाई करते नजर आए हैं।

किसानों को देशद्रोही बताकर व लव जिहाद को मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान भटका रही सरकार : विवेक तन्खा

जबलपुर

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मीडिया से बात की और वर्तमान चर्चित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किसान आंदोलन, कोरोना संक्रमण, लव जिहाद, बेरोजगारी व कांग्रेस के रिवाइवल समेत कई मुद्दों पर केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार कर रही है। किसानों के मूल मुद्दों को दरकिनार कर कहीं उन्हें खालिस्तान समर्थक,माओवादी, देशद्रोही कह रही है। जबकि ऐसा नहीं है, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ना केवल पंजाब के बल्कि पूरे देश के किसान शामिल हैं। मध्य प्रदेश के किसान नेता भी इस आंदोलन में शामिल हैं। किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्काजी का नाम तो उस सूची में भी शामिल था, जिन किसानों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था।विवेक तन्खा का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को खुश करने के लिए बनाया है। किसानों का हक मारा जा रहा है। लिहाजा किसान दुखी है और सड़कों पर है। मोदी सरकार को इन कानूनों में परिवर्तन की इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि इन पर किसी सदन में बहस नहीं होने दी। यदि सदन में बहस के बाद कानून बनाए जाते तो शायद

इतना विरोध नहीं होता। केंद्र सरकार कॉर्पोरेट जगत को खुश करने के लिए इन कानूनों को बनाए रखना चाहती है।विवेक तन्खा का आरोप है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारें जनता के साथ धोखा कर रहीं हैं। जब लोग कोरोना वायरस जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आए दिन कई लोग जान गवां रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट हैं। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि वो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद के कानून पर बहस कर रहीं हैं। जबकि यह बेहद व्यक्तिगत मामला है।विवेक तंखा ने कहा कि शादी एक निजी मामला है। महिला को किसके साथ शादी करनी है,यह उसका अधिकार होना चाहिए।लव जिहाद के कानून से महिला के इस अधिकार का हनन होगा। जो महिलाओं का सशक्तिकरण करने की बजाय उन्हें कमजोर करेगा।

देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, कोरोना संकट विकराल रूप लिए सामने खड़ा है और सरकार लव जिहाद जैसे मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।विवेक तन्खा ने कहा कि देश में प्रजातंत्र बनाए रखने के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस का रिवाइवल होगा। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। अभी कोविड की वजह से संगठन के चुनाव नहीं हो पाए थे। जल्द ही ये चुनाव भी संपन्न होंगे। कांग्रेस कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

आखिर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने क्यों झोंकी इतनी ताकत?

नई दिल्ली। मंगलवार को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों के लिए मतदान संपन्न हुआ। नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। यह देश का पहला नगर निगम का चुनाव था जिसमें देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री तक ने प्रचार किया। आखिर इन चुनाव में इतना क्या दांव पर लगा है भाजपा के लिए? इन चुनावों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इस बदली हुई भाजपा के लिए हर चुनाव एक युद्ध की तरह है जिसे वह हर हालत में जीतना चाहती है।

सामान्यता विधानसभा तो दूर लोकसभा उपचुनाव में भी किसी राष्ट्रीय पार्टी के केंद्रीय नेता प्रचार करने नहीं जाते। यह तो महज एक नगर निगम का चुनाव था लेकिन त्रिपुरा विधानसभा में शून्य सीटों से अचानक सरकार बना लेना, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4 सीटों से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाना और जम्मू-कश्मीर में सरकार बना लेना, यह केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की भाजपा के लिए संभव है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव इसी नजर से देखा जाना चाहिए। तेलंगाना के पिछले विधानसभा चुनाव महज एक सीट जीतने वाली पार्टी आज सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) को हैदराबाद नगर निगम जीतने के लिए चुनौती दे रही है। जाहिर है कि अगला कदम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे। जैसे यह कर्नाटक में अब अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुकी है।चार जिलों के 150 डिवीजन में हुए चुनावों में कुल 1,122 उम्मीदवार मैदान में थे।

बल्लेबाज विधायक का सख्त लहजा

ठेकेदार से कहा-सरकारी स्कूल का निर्माण अच्छे से करना है इसलिए माला पहना रहा हूं

इंदौर

नगर निगम कर्मचारियों पर बल्ला चलाने वाले भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय अब अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कामों में क्वालिटी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि मंगलवार को क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने ठेकेदार को नसीहत देते हुए चेतावनी दे डाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का काम करना है, इसलिए अभी माला पहना रहा हूं। बाकी जो समझना-समझाना है तो मेरे ऑफिस आ जाना। वहां विस्तार से चर्चा कर लेंगे।दरअसल मंगलवार को विधायक आकाश विजयवर्गीय विधानसभा क्रमांक-3 के वार्ड नंबर 55 में शासकीय कन्या विद्यालय के भवन के नवनिर्माण का भूमिपूजन करने पहुंचे थे। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल के भूमि पूजन के अवसर पर उन्होंने शिक्षाविद दीपक खरे के अलावा स्कूल निर्माण का ठेका लेने ठेकेदार को बुलाया और हार पहनाते हुए मंच पर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल को अच्छी क्वालिटी का बनाना है इसलिए हार पहना रहा हूं। हम इस सोच से काम कर रहे है कि हमारे सरकारी स्कूल शिक्षा, साधन, सुविधा और स्तर के मामले में प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाया जा सके।युवा विधायक ने कहा कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार से निवेदन है कि स्कूल शानदार बनाओ, कमी मत छोड़ना। इसमें कोई काम की अनुमति नहीं है, तो उसे बताओ, मैं स्वीकृत करवाकर लाऊंगा। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल है, तो जो मिल रहा है, बना दो। कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ और जोड़ना हो तो वह भी जोड़ो। यह सोचकर स्कूल बनाओ कि आपके बच्चे इसमें पढ़ेंगे। बस, कमरे-कमरे बनाकर मत छोड़ना।आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था नहीं होने से टीचर वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे। बीजेपी सरकार आने के बाद सड़कों का जाल बिछा। इसके बाद टीचर स्कूल जाने लगे हैं। कोशिश है कि सरकारी स्कूल का सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि प्राइवेट स्कूल भी मुकाबला ना कर पाएं।बीजेपी युवा विधायक ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बने सरकारी स्कूलों का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले उन स्कूलों की हालत जर्जर थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला और स्थानीय लोगों के प्रयासों से वहां अब सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर बन सके हैं। आकाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि स्कूल कामकाज पर नजर रखना।

कांग्रेस के सारे सूत्र पड़े खामोश, चारों ओर सन्नाटा

नई दिल्ली

कांग्रेस के तमाम सूत्र खामोश हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। कई वरिष्ठ नेता ऑन रिकार्ड तो दूर, ऑफ रिकार्ड बात करने से भी परहेज कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सूत्रधारों से भरी पार्टी के तमाम सूत्रों ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है?

सोमवार को राहुल गांधी ने असम और तमिलनाडु के पार्टी नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। हालांकि ये किसी चुनाव से पहले संगठन की आम आंतरिक बैठक थी। पर अमूमन ऐसी आंतरिक बैठकों में क्या कुछ हुआ, किसने किसको क्या बोला, किसका रुख कैसा रहा, किसने किसको टोका, किसने किसे क्या समझाने की कोशिश की, कौन किसके साथ खड़ा नजर आया, किसने किसको चुप रहने का इशारा किया, किसने किसकी बात बीच में काट दी, किसने किसका बचाव किया, किसने किसको निशाने पर लिया।।। ऐसी कई बातें सूत्रों के हवाले से छनकर आने की कांग्रेस की परंपरा रही है। कई का खंडन आता था, कई का नहीं। और कई को खंडन के लायक भी नहीं माना जाता था। तो क्या ये परंपरा अब खत्म होने जा रही है? या इस पर तात्कालिक विराम भर लगा है? जो भी है, पार्टी के एक नेता आपसी बातचीत में इस बात की तस्दीक करते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में सभी एक-दूसरे को नए सिरे से आंकने की कोशिश में हैं।

दरअसल अहमद पटेल की कोरोना वायरस की चपेट में आकर हुई असामयिक मृत्यु ने पार्टी नेताओं को कई स्तर पर झकझोर दिया है। भावनात्मक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। पटेल के जाने के बाद पार्टी में एक शून्य पैदा हुआ है। यही शून्य पार्टी के भीतर एक तूफान ला सकता है। खामोशी उसकी पूर्वपीठिका हो सकती है। अहमद पटेल की दुखद मौत के बाद पार्टी फिलहाल मातम में है। इस बीच ऐसी कोई बड़ी राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई है जिससे पार्टी के भीतर की धार का पता चले। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का एक ट्वीट जरूर आया जिसमें वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आए। इससे ये कयास लगाया जाने लगा कि वे बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर आनन्द शर्मा ने स्वयं उस ट्वीट को डिलीट कर दूसरा ट्वीट किया। लिखा कि पहले ट्वीट में वाक्य विन्यास संबंधी कुछ गलती हो गई थी सो अर्थ का अनर्थ हो गया। आनन्द शर्मा, गुलाब नबी आजाद के साथ उन 23 चर्चित नामों में एक हैं जिन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। पार्टी नेतृत्व को लेकर कुछ सवाल पूछे थे, सलाह दी थी और आगे की राह जाननी चाही थी। उसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उन नेताओं को कुछ जवाब भी मिला था। अहमद पटेल ने भी अपने शब्दों में समझाया था। वे न सिर्फ गांधी परिवार और उसके नेतृत्व की ढाल बनकर सामने आए बल्कि अंदरूनी असंतोष पर मिट्टी डालकर आगे की राह भी दिखाने की कोशिश की थी। अब अहमद पटेल नहीं हैं। वे सोनिया गांधी के ऐसे सिपहसालार थे जो पार्टी के असंतुष्टों की सुनते भी थे, उनकी बात आलाकमान के सामने रखते भी थे और दोनों पक्षों को समझाते भी थे। अब वो संबल खत्म हो गया है। तो अब क्या? इस सवाल पर भी तमाम सूत्र खामोश हैं।दरअसल, अहमद पटेल की असामयिक मृत्यु ने पार्टी के सामने दो स्थितियां पैदा की हैं। या तो तमाम असंतुष्ट अब गांधी परिवार की सर्वसत्ता को स्वीकार लें या फिर अपनी अपनी राह लें। क्योंकि सबों को एक सूत्र में पिरोने वाले शख्स का साया उठ गया है। अगर किसी को राहुल गांधी के नेतृत्व से शिकायत है तो क्या अब वे सीधे सोनिया गांधी के पास जाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। तो समय की जरूरत है खामोशी। असंतोष के पुराने स्वरों और बयानों को नया धार देना अभी मुनासिब नहीं। जिन बातों को पार्टी नेतृत्व द्वारा पहले "दिल पर नहीं लिया गया" था, वह जख्म कुरद सकता है। उस जख्म को जड़ से मिटाने का फैसला लिया जा सकता है। इसलिए पहले से चढ़ाकर रखी गई प्रत्यंचा को अभी ढीला छोड़ना ही बुद्धिमानी है। कुल मिलाकर ये कि अब असंतुष्ट कांग्रेसजन अलग राग अलापना बंद कर दें।

अब जो फैसला लेना है वह राहुल गांधी को ही लेना है। पहले कई सूत्र दावा करते रहे हैं कि तमाम फैसले वही लेते हैं। सोनिया गांधी की अंतरिम अध्यक्षता तो एक ढाल मात्र रहा है। अब सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त सिपहसालार और राजनीतिक सलाहकार के न होने से कई फैसलों में उनकी सलाह की कमी नजर आ सकती है। जिन्होंने राहुल गांधी को साधने की कोशिश की थी, वे खुद सध सकते हैं। इसलिए अब उनके सामने की राह यही है कि वे किसी भी तरह के बगावती तेवर को छोड़ें और गांधी परिवार की छत्रछाया में एकजुटता का भरोसा दिलाने की कोशिश में जुट जाएं। हां, जिन असंतुष्टों के पास अपना जनाधार है वह तब भी अलग राह लेने की सोच सकते हैं। मतलब जिन नेताओं ने पहले कभी बड़ी चुनावी कामयाबी हासिल की हो और जिन नेताओं ने किसी राज्य में सत्ता चलायी हो, उनके तेवर अलग हो सकते हैं। वे गांधी परिवार की छत्रछाया से निकलकर अलग मोर्चा बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन जो "पूरी तरह से राज्यसभा धारी हैं उनके लिए फैसला मुश्किल होगा। खासतौर पर तब, जब राज्यसभा जाने का कोई वैकल्पिक दरवाजा खुला न हो। किसी दूसरी पार्टी के लिए उनकी उपादेयता न हो। और अपनी पार्टी में एकजुट दबाव समूह बनाए रखने के लिए कोई नेतृत्व न हो। ऐसे में मन मसोसकर रह जाने के अलावा कोई चारा नहीं।49 साल कांग्रेस को देने वाले जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल के चले जाने पर कहते हैं कि यह अत्यंत दुखद और असामयिक है।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर भारी पड़ा अपना ही ट्वीट, कुछ पल में बदले

नई दिल्ली। कांग्रेस नेतृत्व ने अब पार्टी उन नेताओं पर कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है, जो पार्टी लाइन के बाहर जा कर पार्टी लाइन के विपरीत बयान जारी करेंगे।नेतृत्व के कड़े रुख का खुलासा उस समय हुआ जब पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को आनन-फानन में अपने उस ट्वीट को दुरुस्त करना पड़, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन निर्माता कंपनियों के दौरे को लेकर मोदी की शान में कसीदे पढ़े थे।ट्वीट जारी होते ही कांग्रेस आलाकमान को जब इसकी जानकारी मिली तो 10 जनपथ से आनंद शर्मा को फोन पहुंचा इस चेतावनी के साथ कि अगर उनको अलग रास्ता चुनना है तो चुन लें, पार्टी में रहकर उनको पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आनंद शर्मा के लिये यह बड़ा झटका था, उन्होंने सफाई देते हुये आलाकमान को भरोसा दिया कि वह तत्काल अपने ट्वीट को दुरुस्त कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में आनंद शर्मा ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें मोदी की जगह वैज्ञानिकों की तारीफ की। दरअसल आनंद शर्मा उस ग्रुप 23 के सदस्य हैं, जिसने नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठा कर पार्टी में कोहराम मचा दिया था। सूत्र बताते हैं कि आनंद की बेचैनी का यह बड़ा कारण बना हुआ है।

ईवीएम का प्रदर्शन एवं संचालन की दी जानकारी

माही की गूंज, अलीराजपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता के दिशा निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सेन्स गतिविधि नोडल अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में जिले में सेन्स गतिविधियों का आयोजन किया जाकर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। सेन्स गतिविधियों के तहत मैदानी अमले द्वारा ईवीएम मशिनों का प्रर्दान एवं संचालन की जानकारी देकर आमजन, ग्रामीणों को जागरूक करते हुए ईवीएम की जानकारी प्रदान की जा रही है।

आधार कार्ड के लिए निर्धारित शुल्क का ही भुगतान करें- कलेक्टर सिंह

माही की गूंज,झाबुआ। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा सम्पूर्ण जिले स्तर पर पात्र आवेदकों के आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदक अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार की आधार से संबंधित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सिंह ने अवगत कराया कि नवीन पंजीयन निःशुल्क, बॉयोमेट्रिक के साथ नाम, पता, जन्म दिनांक में संशोधन के लिए शुल्क 100 रूपए, केवल नाम, पता, जन्म दिनांक में संशोधन के लिए 50 रूपए का शुल्क तथा कलर प्रिंटआउट के लिए 30 रूपए शुल्क निर्धारित है। जिले के नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं और परिवार के सदस्यों का पंजीयन अवश्य करवाए। पेन कार्ड वोटर कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस तथा अन्य शासन द्वारा निर्धारित दस्तावेज बनाने का स्थान अपने नजदीकी संकुल केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जाकर बनवा सकते है।

भ्रष्टो का बोलबाला ऐसा कि आमजन को भी गुमराह कर रहे जवाबदार अधिकारी

माही की गूंज, खवासा/भामल।

हमारी कलम सदैव ही भाजपा सरकार के अधीन कार्य करने वाले प्रशासक के बारे में लिखते आई है कि, भाजपा सरकार में प्रशासन पर कोई नियंत्रण नही नतीजन भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि शायद हम कितना भी लिखें वह कम ही पड़ेगा।

एक छोटा सा मामला ग्राम पंचायत भामल में बन रहे 4 लाख 63 हजार के सीसी मार्ग का है, जो मार्ग गांव की एक सकरी गली में गांव के विकास के रूप में सीसी मार्ग बनाने का है। बबलू के घर से बाबू पटेल के घर तक बनाने वाला उक्त सीसी मार्ग के कार्य की स्थिति व अधिकारियों की कार्यप्रणाली दोनों को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि, पंचायत में बैठे सरपंच (प्रधान), सचिव से लेकर इंजीनियर, सीईओ से लेकर वरिष्ठ अधिकारी ही मिलीभगत एवं राजनीतिक संरक्षण के साथ किस तरह से भ्रष्टाचार को बडावा देकर आम लोगों को गुमराह कर रहे है, इस छोटे से विकास कार्य में ही देखने को स्पष्ट रूप में मिल रहा है। उक्त मार्ग का 1 सप्ताह पूर्व ही कार्य चालू हुआ और इस्टीमेट के विपरीत कार्य करने की पुष्टि कार्य के दौरान सब इंजीनियर माइकल डोडियार व थांदला जनपद पंचायत सीईओ रामचंद्र हालू की मौके पर पुष्टि होने के बाद भी गुणवत्ता विहीन व इस्टीमेट के विपरीत निम्न स्तर का कार्य किया जा रहा है।

मामला कुछ युं है कि, सड़क निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री सीमेंट, गिट्टी व रेत का घोल इस्टीमेट के अनुसार कर इस्टीमेट के अनुसार ही लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में बनाना होता है, परंतु यहां रेत के स्थान पर चुरी का उपयोग व घोल में सीमेंट कम मात्रा में होकर बड़े व बोल्ड पत्थर को घोल में डालकर बिना साफ-सफाई व बिना बेस लेवलिंग के सड़क मार्ग बनाने की शुरुआत की थी। उक्त निर्माण की शुरुआत के दूसरे दिन ही मौके पर दौरे के दौरान सीईओ रामचंद्र हालु व सब इंजीनियर माइकल डोडियार ने निर्माण का मुआयना किया तो, रेत की जगह मिट्टी युक्त चुरी के साथ वह सारी अनियमितताएं देखी गई जिसमें सीमेंट की मात्रा घोल में कम होना, सड़क का बिना साफ-सफाई व बिना बेस लेवलिंग के ही सड़क का निर्माण व निर्माण कार्य में बोल्ड पत्थरों को मिलाना के साथ सड़क का लेंथ को भी इस्टीमेट के विपरीत देखा गया। जिसके बाद पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर कोई पंचनामा भी नहीं बनाया गया, वहीं मौके पर अपनी अधिकारी पावर बताते हेतु आम लोगों को गुमराह करते हुए कार्य में अनियमित्ता पाई जाने का कहकर इस्टीमेट अनुसार कार्य करने एवं रेत की जगह मिट्टी युक्त चुरी का उपयोग नहीं कर रेत के उपयोग के साथ सड़क निर्माण के मौखिक निर्देश दिए और उक्त कार्य को रेत के आने तक निर्माण नहीं करने के निर्देश भी दिए गए थे। परंतु अधिकारियों की मिलीभगत के साथ आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयत्न किया जाता है, वह उक्त मौखिक निर्देश के 3 दिन बाद मौके पर माही की गूंज ने देखा, जहां अधिकारियों के निर्देश के बाद भी उसी तरह के निम्न स्तर का कार्य व रेत के स्थान पर मिट्टी युक्त चुरी का इस्तेमाल होकर सड़क निर्माण का कार्य पंचायत के द्वारा खड़े किए गए मेड बहादुर डामर व राजेश उर्फ पप्पू निनामा द्वारा करवाया जा रहा था।

उक्त अनियमित्ता एवं अधिकारी द्वारा सड़क निर्माण बंद करने के निर्देश के बाद भी निम्न स्तर का कार्य क्यों किया जा रहा है पूछने पर पंचायत द्वारा खड़े किए गए बहादुर ने हमारे प्रतिनिधि को स्पष्ट व सार्वजनिक रूप से कहा कि, एक पत्रकार को 5 हजार रुपया दई दिदा है सरपंच साब ने, तो तमाने भी पइसा चिये कई, पइसा चिये तो सरपंच साब ने सचिव कन जाओ वि पइसा तमाने भी दई देगा पर तमे समाचार मत छाप जो, हां साब काम करवा को ना कई गया था पर सरपंच साब का केवा से ऐसो काम चली रो है, हमारे प्रतिनिधि को कहा।

निर्माण को लेकर सचिव दरियावर सिंह माल से बात की तो बताया, सीईओ व इंजीनियर साहब ने 3 दिन पहले ही आकर बारीक चुरी एवं गिट्टी मिट्टी युक्त होने के कारण कार्य को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और अच्छी रेत मंगाने के बाद ही कार्य शुरू करने की बात कही थी यह सही है, निर्माण कार्य को बंद भी कर दिया था और अभी भी कार्य बंद है।

सचिव साहब कार्य तो अभी भी चालू है व निम्न स्तर व बीना रेत के ही मिट्टी युक्त गिट्टी व चुरी से निर्माण किया जा रहा है जिस पर सचिव कहता है, मुझे नहीं मालूम निर्माण चालू है और यह भी नहीं मालूम कि कार्य किसने चालू करवाया।

सरपंच पति नागु से बात की तो बताया, काम करवा रहे छोरों ने यह गलत बात कही कि किसी पत्रकार को पैसे दिए हैं, यह सही बात है कि बिना रेत के काम बंद करने के निर्देश सीईओ व इंजीनियर साहब ने दिए थे पर गांव वालों के कहने पर बिना रेत के ही कार्य कर रहे हैं, यह सही है काम में थोड़ी गलती है तमे समाचार मत छाप जो मै तमा से आई ने मिल लूंगा, कहकर माही की गूंज को अपनी तरह भ्रष्ट समझ कर अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन देने की बात कही।

अपने विभाग की छवि धूमिल करने में लगे हुए है रिश्वतखौर आबकारी व पुलिस के अधिकारी

आबकारी इंस्पेक्टर ने अपने विश्वसनियों के माध्यम से प्रलोभन से न माने तो पत्रकार को मानहानी के दावे की दी धमकी

माही की गूंज, डेस्क न्यूज शुजालपुर।

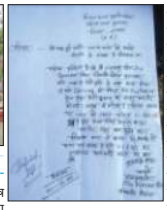

जब आमजनो की सुनवाई व माफियाओ व अनियमित्ताओ के विरूद्ध जवाबदारो द्वारा रिश्वतखोरी के साथ अपने कर्मनिष्ठा की पूर्ति नही की जाती है तो आमजन पुरी अपेक्षा के साथ पत्रकार को अपने हक की लडाई व आमजन की समस्या को सार्वजनिक कर न्याय दिलाने के उदेश्य से सुचना देता है व एक निष्पक्ष पत्रकार से पुरी उम्मीद कर समस्या बताता है और वो पत्रकार आमजन की आवज बन अधिकारीयो को अवैध व्यापार व क्षेत्र में हो रही अनियमित्ताओ को सुधारने की बात करता है और वह अपनी लेखनी के माध्यम से वस्तु स्थती सार्वजनिक करता है तो भ्रष्ट अधिकारी नित नए तरीको से माफियाओ एवं अपराधियो के माध्यम व अपने विश्वसनियतो के माध्यम से पत्रकार को धमाकने व मौका आने पर उसके विरूद्ध झुठे मामले दर्ज करने में कोई चुक नही करते है।

ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिले के शुजालपुर के माही की गूंज के पत्रकार अजय राज केवट के साथ हो रहा है जिसमें आबकारी अधिकारी व पुलिस अधिकारी को आमजन की सुचना पर अवैध शराब विक्रय की जानकारी मांगने व देने पर व कार्रवाई नही करने पवर मामले को प्रमुख्ता के साथ माही की गूंज में समाचार प्रकाशित होने पर ''खिस्यानी बिल्ली खम्बा नौचे'' की तर्ज पर प्रलोभन देने व जनहित के लिए प्रलोभन न स्विकारने पर मानहानी की धमकिया भी देने में पिछे नही हट रहे है। बतादे कि, पिछ्ले अंक में गूंज में ''गांव-गांव व ढाबो पर चल रहे शराब के अवैध मयखाने'', ''कारस्तानीः कार्रवाई के बजाए आबकारी इंस्पेक्टर मिनाक्षी अवैध शराब की सुचना देने वाले एवं जानकारी मांगने वाले पत्रकार कि सुचना माफिया को देकर धमकाने का कर रही कार्य'' के शिर्षक के साथ प्रकाशित समाचार के बाद आबकारी की महिला इंस्पेक्टर ने अपने विश्वसनीय व्यक्ति को पत्रकार के पास भेज माही की गूंज में अवैध शराब माफियाऔ के कारोबार व आबकारी की मिलीभगत के समाचार आगे से प्रकाशित न करने हेतु प्रलोभन देने का प्रथम प्रयास किया जब गूंज प्रतिनिधी ने रिश्वतखौर अधिकारी के प्रलोभन को स्वीकारने से मना करने पर मानहानी के दावे की धमकी दी गई लेकिन मेडम साहिबा माही की गूंज की टिम जनहित के लिए माफियाओ व आपकी कारस्तानियो को उजागर करने में कतई पिछे नही रहेगी हां आप हमें जितने दावे व नोटिस दे हम फिर भी तथ्यात्मक रूप से जो भी समाचार होंगे चाहे आप हो या आपके अधिकारी हमारी कलम ऐसे ही निरन्तर बैबाकी के साथ आमजन के हितो के लिउ चलती है और चलती रहेगी।

वही जब आमजन की अपेक्षा अनुरूप आबकारी इंस्पेक्टर ने शराब माफियाओ के साथ अपनी मिलीभगत के चलते कार्रवाई नही करने पर क्षेत्र के आमजन ने पुलिस पर अपेक्षा कर पत्रकार को क्षेत्र में होटलो एवं ढाबो पर बिक रही अवैध शराब की जानकारी दी, उक्त तथ्यात्मक जानकारी के बाद अवैध शराब बिक्री की सुचना आमजन की विश्वसनियता पर खरा उतरते हुए पुलिस को दी। सुचना मिलने के बाद आमजन के साथ पत्रकार को भी पुलिस अधिकारी गुमराह करते हुए पत्रकार को कार्रवाई हेतु जा रहे है कहते रहे और थाने से निकलकर अधिकारी ढाबो पर बिक रही अवैध शराब पकडने के बजाए ढाबो से दुर खडेरहकर अवैध शराब बिक्री करने वाले ढाबे संचालक को सुचना दे दी कि, हम शिकायत पर दबिश देने आ रहे है आप जो भी शराब ढाबे पर है हटा दे। वही पुलिस की उक्त कारस्तानी पत्रकार के मुखबिर द्वारा पत्रकार को दी जा रही थी करीब ढेड घंटे बाद पत्रकार ने पुलिस की कार्रवाई सम्बंधि जानकारी समाचार संकलन हेतु मांगी तो कहने लगे हम अब जा रहे है तो पत्रकार ने मुखबिर की सुचना के आधार पर पुलिस अधिकारी को कह दिया कि, साहब आपको कार्रवाई नही करना हो तो हमे कोई दिक्कत नही पर मुखबिर की सुचना पर मैं एसपी साहब को जानकारी दे देता हु उक्त बात के बाद साहब ढाबे संचालक को सुचना देने एवं वहा से अवैध शराब हटाने के साथ ढाबे पर शराब पिने वाले शराबियो को भी रवानगी देने के बाद साहब अपनी टिम के साथ कार्रवाई का ढोंग कर ढाबे पर पहुचे और अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रतिनिधी को वाट्सअप विडीयो कांल कर ढाबे पर किसी प्रकार की कोई शराब नही है कहते हुए ढाबे का विडीयो लाईव दिखाने का कृत्य कर पत्रकार की जान-माल को खतरे में डालने का कुकृत्य किया गया। बता दे कि, पुलिस को ट्रेनिंग में मुखबिर या सुचनाकर्ता का नाम किसी भी स्थिती में सार्वजनिक करने का नही होता है और अपराध दर्ज होने के बाद न्यायालय भी पुलिस से बयान के दौरान मुखबिर का नाम नही पुछती है उस दिशा में एक जवाबदार अधिकारी द्वारा यह कृत्य किया गया की ढाबे पर जाकर सम्बंधित सुचनाकर्ता का नाम अवैध शराब विक्रेता के समक्ष सार्वजनिक करने के बाद विडीयो काल भी लगाकर सुचनाकर्ता की तथ्यातमक रूप से रिश्वत खोरी एवं मिलीभगत के साथ पुलिस ने सुचनाकर्ता की जान को खतरे में डालने का प्रयास किया है जिसकी पत्रकार जगत व माही की गूंज परिवार निंदा करता है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई नही की जाति है तो वह भी निंदनिय है।

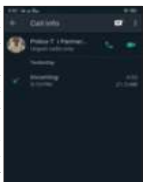

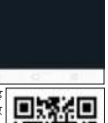

– पुलिस की कारस्तानी कि हकिकत क्युआर कोड स्कैन कर देखे विडीयो।

मनमानी करने के लिए अधिकारी कलेक्टर को भी गुमराह करने से नही चूकते

माही की गूंज, पेटलावद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बामनिया में पदस्थ एक मात्र स्टाफनर्स शुभांगी शर्मा का नियम विरुद्ध किए पेटलावद अटैचमेंट को समाप्त कर मूल अस्पताल में भेजने के लिए जिला कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत के बाद कलेक्टर स्टाफनर्स का तत्काल अटैचमेंट करने का पत्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा गया जिस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने नियम विरुद्ध हुए अटैचमेंट समाप्त करने के बजाए कलेक्टर को गुमराह करते हुए पेटलावद सिविल हॉस्पिटल में 30 नर्स की आवश्यकता के अनुरूप वर्तमान में 23 नर्स की कमी बताकर बामनिया में एक सविंदा नर्स और एक एएनएम होने का हवाला देकर प्रशासनिक आधार पर ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल में लगाई जाने की झूठी जानकारी बनाकर जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दी।

नही शुरू हुआ सिविल हॉस्पिटल, नई स्थाई स्टाफनर्स ने भी ड्यूटी कर ली जांइन

कलेक्टर को भेजे पत्र में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बामनिया की स्टाफ नर्स को सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में ड्यूटी लगाना बताया, जबकि वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल पेटलावद अभी शुरू ही नही हुआ है। स्टाफनर्स शुभांगी शर्मा वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद में ही ड्यूटी कर रही है। पेटलावद सामुदायिक केंद में किसी प्रकार की स्टाफनर्स की कोई कमी नही है और गत दिनों पेटलावद पदस्थ हुई नई स्टाफनर्स कल्पना कटारा भी जांइन कर चुकी है।

नही है अटैचमेंट के अधिकार

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को किसी का भी अटैचमेंट करने का कोई अधिकार नही है शासन के आदेशानुसार बिना प्रभारी मंत्री या कलेक्टर की अनुशंसा के विभाग में किसी का भी अटैचमेंट नही किया जाना है, बाबजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बड़ी लेंन-देंन कर कर्मचारियों और डॉक्टरों तक को मन चाहे स्थान पर नोकरी करने के लिए नियम विरुद्ध अटैच कर रहे है। शिकायत होने के बाद भी अधिकारी जिला कलेक्टर को गुमराह कर गलत जानकारी देने से भी नही चूकते। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी जयपालसिंह ठाकुर से चर्चा की गई तो खुद के कार्यालय और खुद के हस्ताक्षर से कलेक्टर को प्रेषित पत्र की जानकारी नही होना और मामले को दिखाने की बातकर टाल-मटोल करने लग गए और इस विषय पर कोई जवाब नही दे सके।

भ्रष्टाचार करने वाली तारखेड़ी पंचयात के नुमाईदों को अपर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

जनपद स्तर पर चल रही जांच का नही हुआ अब तक कोई निराकरण, जांच के नाम पर हो रही केवल वसुली

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर करोड़ो की राशि का आबंटन प्रति वर्ष होता है, लेकिन विकास गाँव का कम और सरपंच, सचिव ओर रोजगार सहायको का होता है, पिछ्ले दस वर्षों में पंचयात से दस से बीस हजार का वेतन पाने वाले सचिव और रोजगार सहायको ने अचूक संपत्ति बना ली तो सरपंचों ने भी अपने व्यारे-न्यारे कर लिए है, एक समय था जब केवल कमीशन पर काम हो जाते थे, लेकिन जैसे-जैसे बढ़ती योजनाओं के माध्यम से राशि आना शुरू हुई पंचायतो से जुड़े सरपंच और कर्मचारियों ने कागजो पर कार्यो को करके शासन द्वारा दी गई पूरी की पुरी राशि उड़ा ली, विकास खण्ड की एक-दो नही लगभग हर पंचायत में इस प्रकार के मामले लगातार उजागर हो रहे है, लेकिन बंदरबाट के इस खेल में हर कोई डुबकी लगा रहा है, जो जिम्मेदार लूट में शामिल थे उन्होंने कोई कार्रवाई नही की और जिनको शिकायत की उन्होंने जांच के नाम पर बहती गंगा में हाथ धो लिए, जब कि मामला सीधे-सीधे अपराध और गबन का है जिस पर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज होने थे लेकिन जांच के नाम पर प्रमाणित हो चुके भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है।

अपर कलेक्टर झाबुआ ने दिया तारखेड़ी पंचयात को नोटिस

विश्वमंगल हनुमान के नाम से प्रसिद्ध धाम वाली ग्राम पंचायत तारखेड़ी में मन्दिर से रावला तक बनने वाले 5 लाख की लागत का सीसी रोड वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुआ था, ग्राम पंचायत ने रोड निर्माण के फर्जी बिल और फ़ोटो लगाकर चार लाख से भी अधिक की राशि निकाल ली, मामले की शिकायत अधिकारियों को की जा चुकी है। मीडिया के माध्यम से पूरा मामला उजागर हो चुका है, मामले की जांच भी हो गई जिसमें खुल्ले तोर पर भ्रष्टाचार पाया गया, बिना कार्य किए फर्जी बिलो से राशि आहरण करना भी सिद्ध हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अब तक भ्रष्टो को जांच के नाम पर घुमा कर वसुली कर रहे है। मामले में 27 नवम्बर को न्यायालय, अपर कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी झाबुआ द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच(प्रधान) तेजमल सिंगाड, सचिव हेमन्त गरवाल को नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में भ्रष्टाचार सिद्ध होने का पूर्ण उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायत को मप्र पंचायत राज स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत राशि वसुली की कार्रवाई की गई थी जिसका कोई निराकरण नही हुआ है, जिसे न्यायलय अपर कलेक्टर ने धारा 89 के तहत शासकीय कार्यो में लापरवाही, कर्तव्यों का दुरुपयोग कर अनियमित्ता करने सहित पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना प्रस्तावित कर 3 दिसम्बर को न्यायलय के समक्ष पेश होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि न केवल ग्राम पंचायत से रोड का निर्माण करवाया जाएगा साथ ही भ्रष्टो पर वैधानिक कार्रवाई भी होगी।

जिला पंचायत में भी चल रही है जांच

मामला उजागर हुए 6 माह से अधिक समय बीत चुका है जांच भी हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल भ्रष्टो को फुटबाल बनाकर टाइम पास किया जा रहा है कभी धारा 40 तो कभी धारा 92 के नोटिस पर जवाब और तारिख पर तारिख देकर जबरन समय व्यतीत किया जा रहा है। अधिकारियों की कार्रवाई का कोई खोफ या डर पंचायत के सरपंच-सचिव को नही है, उल्टा नए भ्रष्टाचार करने में जुट गए, भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद भी अपराध दर्ज नही होना स्वतः ही अधिकारियों की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

चोरी करो पकड़े जाओ तो, चोरी का आधा-अधूरा माल जमा करो और बच जाओ

वैसे तो कानून के हिसाब से चोरी करना अपराध है और उसके लिए कई धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। शासकीय राशि की चोरी, दुंरूपयोग, भ्रष्टाचार के लिए तो और भी गंभीर धाराएं कानून की किताब में दर्ज है, लेकिन झाबुआ जिले में आकर सारे कानून धरे रह जाते है और सब मिलकर चोर ओर चोरी करने वाले को बचाने में जुट जाते है जिसके लिए तगड़ी माल वसुली ओर भेट पूजा होती है। जिम्मेदार ग्राम पंचायतो के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की बजाए चोरी की गई राशि वसूल कर फर्जी निर्माण को पूरा करने का दबाव बनाकर मौके पर जैसा-तैसा घटिया निर्माण करवाया जाता है और मामला राशि वसुली ओर निर्माण बताकर बन्द कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार के नाम पर एक ओर भ्रष्टाचार ओर आने वाले समय के लिए भ्रष्टो को खुली छूट के लाइसेंस जारी किए जाते है।

संपादकीय

किसान संगठन को रोकने के सरकार के बर्ताव सराहनीय नही

किसानों के दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकार ने जो तरीके अपनाए, वो हैरत में डालने वाले हैं। ज्यादा हैरत इसलिए हुई क्योंकि ये किसान किसी पार्टी या एक संगठन से जुड़े हुए नहीं थे। इसकी आंदोलन की पहचान विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन की है। किसान कथित कृषि सुधार के तीन कानूनों और प्रस्तावित नए बिजली कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, तो क्या उन्हें विरोध जताने का हक नहीं है? क्या देश में लोकतंत्र औपचारिक रूप से खत्म हो चुका है? और फिर जिस तरह के तरीके अपनाए गए, उनका क्या तुक है? इतना ही नहीं, सरकार प्रेरित प्रचार तंत्र ने इन किसानों को खालिस्तानी, नक्सली और विपक्षी साजिश का हिस्सा तक बता दिया। क्या सरकार ऐसा करके देश में घुटन का माहौल नहीं बना रही है?

गौरतलब है कि हरियाणा में अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लोहे के बैरिकेड्स लगाए। इस दौरान पुलिस ने किसानों को पुल पर ही रोकने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। किसानों पर ठंडे पानी की बौछार की। फिर भी किसानों पर इन सब कार्रवाइयों का असर नहीं हुआ। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ कर नदी में फेंक दिया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर, ट्रॉला अन्य वाहनों पर सवार हो कर दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर दबाव बनाने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न धड़ों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया है। किसान अपने साथ राशन और पानी लेकर चल रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें जहां रोकेगी वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल और पंजाब के किसान करीब दो महीने से 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। किसान कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 का विरोध कर रहे हैं और इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार अगर उन्हें दिल्ली आकर अपनी बात कहने देती तो उससे कोई आसमान नहीं टूट जाता। लेकिन देश ने कुछ अलग नजारा ही देखा।

चाणक्य नीति

अगर हो सके तो विष मे से भी अमृत निकाल लें, यदि सोना गन्दगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाये, धोएं और अपनाये, निचले कुल मे जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें, उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणो से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें।

किसान मुद्दा- किसानों पर बरस रही है लाठियां!

कृषि विधेयक के खिलाफ पंजाब-हरियाणा के किसानों का हल्ला बोल जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पंजाब से किसानों के दल हरियाणा में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली की दो सीमाओं के निकट पहुंच गए। किसानों ने केन्द्र के कृषि कानूनों के विरोध में 'दिल्ली चलो' मार्च का आह्वान किया है।

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु बॉर्डर पर बालू से भरे ट्रक और पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां तैनात कर दी गई। साथ ही कंटीले तारों से बाड़ भी लगाई गई। इसके बावजूद, किसानों के दो समूह सिंघु और टीकरी बॉर्डर के पास पहुंच गए और जिसपर दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

हरियाणा के भिवानी में सड़क दुर्घटना में एक किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्राली के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह हादसा हुआ। हादसे में 40 साल के किसान तन्ना सिंह की मौत हो गई। तन्ना सिंह पंजाब के खयाली चहला वाली जिला मानसा थाना चनीर (पंजाब) का निवासी था। किसानों ने पुलिस को शव कब्जे में नही लेने दिया।किसान आंदोलन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम मांगे हैं। स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाया जाएगा। जिनमें किसान आंदोलन में गिरफ्तार किसानों को रखा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 'हम आंदोलन तेज करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार अभी किसानों से बात करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से बात करें और उन्हें आश्वासन दिलाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसानों पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा किसानो की। अब मुजफ्फरनगर में सड़क जाम होगी और आगे हरियाणा का रुख देखते हुए आगे की स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा।'

किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम मूल्य समर्थन प्रणाली समाप्त हो जाएगी। वहीं किसान यदि पंजीकृत कृषि उत्पाद बाजार समिति-मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। साथ ही ई-नाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा? इस विषय पर सरकार मौन है। हालांकि मोदी सरकार इन तीन कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है तो किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ हैं और वे सड़क और सोशल मीडिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जबकि लोकसभा व राज्यसभा में तीनों बिल पास हो गए हैं। बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी, कुछ शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं लेकिन इसे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। परन्तु यह सब पारित विधेयकों में व्यवस्था नहीं दी गई। इसी लिए विरोध हो रहा है। किसानों को लग रहा है सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है। किसानों को लगता है सरकार का यह कदम किसान विरोधी है।

बीती 17 सितंबर को लोकसभा में दो बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लोक सभा से पारित हुआ, जबकि एक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। यह अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन जिन किसानों के पास मोल-भाव करने की क्षमता नहीं है, वे इसका लाभ कैसे उठाऐंगे?

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वीएम सिंह भी विधेयक की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वे कहते हैं, 'सरकार एक राष्ट्र, एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पायेगा। क्या किसानों के पास इतने साधन हैं और दूर मंडियों में ले जाने में खर्च भी तो आयेगा।'

इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा फसल बेचने के तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार-बार चक्कर काटने होंगे। न तो दो-तीन एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है और न ही वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। इसी कारण किसान इन बिलो के विरोध में है।'

कृषि मामलो विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं, 'जिसे सरकार सुधार कह रही है वह अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में पहले से ही लागू होने बावजूद वहां के किसानों की आय में कमी आई है। अमेरिका में सन 1960 के दशक से किसानों की आय में गिरावट आई है। इन वर्षों में यहां पर अगर खेती बची है तो उसकी वजह बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता है।' बिहार में सन 2006 से एपीएमसी नहीं है,जिसका फायदा उठाकर व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर खाद्यान्न खरीदते हैं और उसी वस्तु को पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर बेच देते हैं । इन विधेयको के खिलाफ कांग्रेस ने संसद भवन में गांधी स्टैचू पर धरना दिया और कहा कि यह काला कानून है। इससे किसान को नुकसान होगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है।

श्रीगोपाल नारसन

उनकी राय में इस व्यवस्था से किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे। इन बिलों में कहीं भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी गयी है। मंडी कुछ बड़े लोगों के कब्जे में होगी और अपनी मनमर्जी से वह फसलों के दाम तय करेंगे। जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शब्दों में, 'किसान ही हैं जो ख़रीदता खुदरा में है और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के तीन 'काले' अध्यादेश किसान-खेतिहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें एमएसपी का लाभ व हक मिलें और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें।' जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वे कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, पंजाब में पैदा होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफसीआई उसे ख़रीदता है। साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए करीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी।किसानों को डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएंगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को करीब 2.5: के कमीशन का घाटा होगा, साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले इन तीनों कृषि सम्बन्धी विधेयकों को लेकर किसानों और किसान संगठनों से चर्चा तक नहीं की गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस विषय पर अन्नदाता किसान को विश्वास में लेना चाहिए था। ऐसा करके किसानों के इस विरोध व बवाल से बचा जा सकता था। दुःखद बात यह भी है कि सरकार अन्नदाता किसान से हाथ फैलाकर मिलने के बजाए उसपर लांठिया भांज रही है, पानी की बौछार छोड़ रही है। यह तो सीधे सीधे किसान का अपमान ही हुआ, जिससे सरकार को बचना चाहिए।

अब जन-दक्षेस का मौका है

यह नवंबर का महिना भी क्या महिना था। इस महिने में छह शिखर सम्मेलन हुए, जिनमें चीन, रुस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान समेत आग्नेय और मध्य एशिया के देशों के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति ने भी सीधा संवाद किया। उसे संवाद कैसे कहें ? सभी नेता जूम या इन्टरनेट पर भाषण झाड़ते रहे। सबने अपनी-अपनी बीन बजाई। सब कोरोना की महामारी पर बोले। सब ने अपने-अपने युद्ध-कौशल का जिक्र किया। सब ने वे ही घिसी-पिटी बातें दोहराईं, जो ऐसे सम्मेलनों में प्रायः वे बोलते रहते हैं। उन्होंने अपने विरोधी राष्ट्रों को भी घुमा-फिराकर आड़े हाथों लिया। असली प्रश्न यह है कि इन शिखर सम्मेलनों की सार्थकता क्या रही ? बेहतर तो यह होता कि भारत अपने पड़ौसी देशों से सीधा संवाद करता। इस संवाद के लिए दक्षेस (सार्क) का निर्माण हुआ था। अब से लगभग 40 साल पहले जब इसके बनने की तैयारी हो रही थी तो हम आशा कर रहे थे कि भारत और उसके पड़ौसी देश मिलकर यूरोपीय संघ की तरह एक साझा बाजार, साझा संसद, साझा सरकार और साझा महासंघ खड़ा कर लेंगे लेकिन यह सपना भारत-पाक तनाव का शिकार हो गया।

इन दोनों देशों के वेबनाव और मनमुटाव के कारण दक्षेस सम्मेलन कई बार होते-होते टल गया। जब हुआ तो भी कोई बड़े फैसले नहीं हो पाए। दक्षेस सम्मेलनों में होता क्या है ? इन देशों के प्रधानमंत्री वगैरह भाग लेते हैं। वे अपने रस्मी भाषण देकर बरी हो जाते हैं और बाद में उनके अफसर उन्हीं भाषणों के आधार पर सहयोग के छोटे-मोटे रास्ते निकालते रहते हैं। सरकारें आपसी सहयोग करते वक्त इतने असमंजस में डूबी रहती हैं कि कोई बड़ा फैसला कारगर ही नहीं हो पाता। तब क्या किया जाए ? मेरी राय है कि दक्षेस तो चलता रहे लेकिन एक जन-दक्षेस (पीपल्स सार्क) भी कायम किया जाए, जिसमें दक्षेस के आठों देशों के कुछ प्रमुख लोग तो हों ही, उनके अलावा म्यामांर, ईरान, मोरिशस, सेशेल्स और मध्य एशिया के पांच गणतंत्रों के लोगों को भी जोड़ा जाए। मैं इन लगभग सभी देशों में रह चुका हूं और वहां इनमें अपनेपन का दर्शन कर चुका हूं। यदि इन 17 देशों के जन-प्रतिनिधियों का एक संगठन खड़ा किया जा सके तो अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, एशिया का यह क्षेत्र यूरोप से अधिक समृद्ध हो सकता है और तिब्बत, कश्मीर, तालिबान आदि मामले भी अपने आप सुलझ सकते हैं। यह सैकड़ों साल से चले आ रहे बृहद् आर्य-परिवार का पुनर्जन्म होगा।

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

काम की बात

सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत।

एक सलाह

हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है।

संयमित और स्वच्छ हो सूचना और संवाद के नए आयाम

वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना और संचार ने हमारे जीवन को रफ्तार दी है। बिना सूचना के वर्तमान समय में जीवन के संचालन की कल्पना करना नामुमकिन सा है। आज न केवल सूचना का प्रारूप परिवर्तित हुआ है, बल्कि सूचना प्रसारण के स्वरूप भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आज चंद पलों में ही सूचना विश्व के कोने-कोने तक पहुंच जाती है। सूचना को प्रसारित करने में इंटरनेट ने अपनी महती भूमिका निभाई है। आज इंटरनेट की पहुंच घर-घर तक हो गई है। ऐसे में यूँ कहें कि पूरी दुनिया एक हथेली में सिमटकर रह गई है, तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह सच है कि सही सूचना जीवन को रफ्तार देती है, लेकिन अगर सूचना ही गलत परोसी जाएं या गलत ढंग से रचकर तथ्यों को सूचना और संवाद के रूप में परोसा जाएं। फिर यह सिर्फ व्यक्ति-विशेष को ही नहीं प्रभावित करेगी बल्कि पूरे समाज में ही वैमनस्यता फैलाने का काम करेगी।

बात करें तो आज इंटरनेट पर सूचनाओं को देखने का स्वरूप भी बदल गया है। साथ ही नए नए प्लेटफार्म उभरकर सामने आ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म (वअमत-जीम-जवच) हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, बूट, जी-5, सोनी लाइव जैसे प्लेटफार्म भी सामने आ गए हैं। कोरोनावायरस और लॉकडाउन के बाद इन प्लेटफार्म पर दर्शकों की संख्या मे भी तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में सवाल यही क्या जिस हिसाब से ये सूचना और संवाद के प्लेटफॉर्म सामने आ रहें, उसी के अनुरूप बेहतर और एक सभ्य समाज का दृष्टिकोण इनकी विषय-वस्तु रखती या नहीं? एक अनुमान के मुताबिक भारत में ओटीटी मार्केट 2023 तक 3.60 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। वोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में यह मार्केट 35 हजार करोड़ रुपए का था। इंटरनेट की बढ़ती रफ्तार से ओटीटी मार्केट 15 फीसदी की रफ्तार से तरक्की कर रहा है। 2025 तक वैश्विक मार्केट 17 फीसदी से बढ़कर 240 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब यह मार्केट वैश्विक स्तर पर विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है, तो इस पर दिखाई जाने वाली सामग्री भी विश्वसनीय और सभ्य हो जिससे युवा वर्ग सही दिशा में तरक्की कर सके। वर्तमान दौर की सच्चाई पर नजर डाले तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वही कंटेंट दिखाते हैं, जो विवादित हो जिससे लोगों की दिलचस्पी इन्हें देखने में बढ़े। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंटेंट का समाज के युवा वर्ग पर क्या असर होगा। आज के दौर की कड़वी सच्चाई को अगर देखें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदू धर्म विरोधी कंटेंट को ही प्रसारित किया जा रहा है। उनका उद्देश्य मात्र यही रह गया है कि किस तरह से धर्म विशेष की आलोचना करके अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ाया जा सके।

आज के दौर में वेब सीरीज का चलन बढ़ता जा रहा है और इन वेब सीरीज पर नजर डाले तो यह केवल एक धर्म विशेष के खिलाफ ही एजेंडे के तहत विवादित कंटेंट प्रसारित करते है। वजह शायद यही है कि हिंदुओं को टारगेट करने की ओछी राजनीति बरसों से ही हमारे देश में चली आ रही है। हमारी संस्कृति हमारी आस्था को पश्चिमी संस्कृति ने हमेशा से ही नीचा दिखाने का प्रयास किया है। हिंदू धर्म की व्याख्या को भी सभी धर्मावलंबियों ने अपने- अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। यही वजह है कि सैकड़ों साल पहले जब मुगल भारत आए तो उन्होंने हमारी आस्था पर ही चोट करने का काम किया। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया यहां तक कि मूर्ति पूजा की भी निंदा की गई। वही जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एकेश्वरवाद की परिभाषा गढ़ दी।

23 जुलाई 2018 को टाईम्स ऑफ इंडिया में छपे आर्टिकल 'महाराष्ट्र गुडमैन फोर्सेज मेन इनटू अन नेचुरल सेक्स, हेल्ड' में फकीर आसिफ नूरी के अपराध की कहानी को छापा गया था, लेकिन तस्वीर एक हिन्दू साधु की लगाई गई थी। इस स्टोरी को मोहम्मद आसिफ नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। जिससे साफ पता चलता है कि कैसे हिन्दूओं के विरोध में कुछ वामी मीडिया संस्थान भी काम करते है। वर्तमान दौर में इस प्रकार के मीडिया संस्थानों की भरमार है। आज टेलीविजन धारावाहिकों को ही देखे तो उनमें केवल और केवल धर्म विरोधी कन्टेंट ही प्रसारित किया जा रहा है। यहां तक कि रियलिटी शो को तो बनाया ही इस उद्देश्य से जाता है जो अश्लीलता फैला सकें। इन कार्यक्रमों को संचालित करने वालो के तर्क भी अजीब रहते हैं। उनका मत है कि जिन दर्शकों को कार्यक्रमों में अश्लीलता महसूस हो वे इन कार्यक्रमों को न देखे। वे देश की युवा पीढ़ी को अश्लील कार्यक्रमों को परोसने में कोई गुरेज नही करते है।

सोनम लववंशी

नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज ने तो मर्यादा की सारी हदों को ही पार कर दिया है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'ए सूटेबल बॉय' के एक दृश्य में नायक नायिका को भगवान के मंदिर में अश्लील हरकतें करते फिल्माया गया है। यहां सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे दृश्य को मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर फिल्माना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इन मीडिया संस्थानों ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कि कैसे हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा सके। यह मनोरंजन कम्पनियां किसी और धर्म के खिलाफ कभी कोई विवादित कार्यक्रम प्रसारित नहीं करती। अब इनका दोहरा चरित्र ही कहे कि ये केवल और केवल हिन्दू विरोधी कंटेंट ही प्रसारित करती है। अब यह उनका डर कहे या फिर हिंदू विरोधी मानसिकता कहे यह तो इन कार्यक्रमों को बनाने वाले ही जाने लेकिन जिस तरह से हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा रही है। उसे देखकर तो यही लगता है मानो यह संस्थान एजेंडे के तहत इस प्रकार के प्रोग्रामों का प्रसारण करते हैं।

हमारे देश में सियासत भी अतरंगी है। राजनीति में नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। सियासत के ठेकेदारों ने धर्म को भी अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार उपयोग करना सीख लिया है। यहां तक कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने में इन्हें कोई संकोच नही होता है। उन्हें तो बस अपना राजनीतिक लाभ दिखता है। फिर चाहे उसके बदले उन्हें अपने धर्म के खिलाफ ही क्यों ना बोलना पड़े। राजनीति में ईमान, धर्म, मान, मर्यादा और आस्था जैसे शब्द बेमानी से लगने लगे हैं। ऐसे में कैसे यह उम्मीद की जाए कि राजनीति के रणबांकुरे हमारी संस्कृति हमारी आस्था को बनाए रखने का, उसे सहेजकर रखने का प्रयास करेंगे। आज के वर्तमान दौर में यह हमें ही तय करना है कि तकनीकी के इस दौर में सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी। ऐसे में हमें अपने मूल्यों को खुद समझना होगा और यह हमें ही तय करना होगा कि हम समाज को किस दिशा में लेकर जाए। समाज में फैली बुराई को किस प्रकार खत्म कर सके। इस दिशा में हमें और हमारे समाज को ही सोचना होगा।

चीन की उकसावे की रणनीति

लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन हमेशा उकसावे वाली रणनीति अपना रहा है। एलएसी पर निर्माण कार्य के बाद अब चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। अगले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। चीन कह रहा है कि बांध बनने से दक्षिण एशियाई देशों से सहयोग के रास्ते खुलेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने चीन से ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते का पालन करने को कहा है। चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। इस बड़े बांध की तैयारी ने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही देश ब्रह्मपुत्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह दोनों देशों के हितों का ध्यान रखेगा। भारत ने चीन के इस कदम का विरोध किया है।

चीन की इस तरह की गतिविधियां उसकी युद्ध की मानसिकता और तैयारियों का संकेत हैं। इससे यह जाहिर होता है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को उकसा कर लड़ाई छेडने की फिराक में है। इस साल मई से लेकर अब तक के घटनाक्रम से भी इसकी पुष्टि होती है। मई महीने में सीमा पर घुसपैठ और मारपीट की घटनाओं की परिणति 15-16 जून की आधी रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के रूप में देखने को मिली, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख दिखाया, जिसे भारतीय सैनिकों की सजगता से नाकाम कर दिया गया था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में भारत को लेकर चीन ने जो रुख दिखाया है, उसका दोनों देशों के संबंधों बुरा असर पड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरों से उम्मीद बंधी थी कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत होगी और सीमा विवाद हल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। पहली बार चीनी राष्ट्रपति सितंबर 2014 में भारत आए थे और दूसरी बार पिछले साल अक्टूबर में। लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फिरने में साल भर भी नहीं लगा। मई से ही चीन ने लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर जिस तरह की घुसपैठ और सैन्य गतिविधियां जारी रखी हुई हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि चीन भारत का अच्छा दोस्त और पड़ोसी हो सकता है। ऐसे में हैरानी पैदा करने वाली बात यह है कि एलएसी पर चीन जो कर रहा है, क्या वही रिश्तों का नया युग है! विदेश मंत्री ने खुद इस हकीकत को स्वीकार किया है कि पैंगोंग में जून में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले ने तीस साल से चले आ रहे सामान्य रिश्तों को खत्म कर डाला। इससे न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर, बल्कि जनता के स्तर पर भी गहरा असर पड़ा है। मुश्किल यह है कि सीमा पर शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भारत-चीन के बीच अब तक जो करार हुए हैं, चीन ने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। दोनों देशों के बीच 1996 में हुए समझौते में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के दो किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। वर्ष 2013 में हुए सीमा रक्षा सहयोग करार में सहमति बनी थी कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने-सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने इन समझौतों को दरकिनार करते हुए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। हाल में उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका बयान दे डाला, जिसका भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया। दरअसल, अब लद्दाख में भारत ने जिस तरह की सैन्य तैयारियां कर ली हैं, उससे भी चीन परेशान है। वह समझ चुका है कि भारत अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने की मजबूत स्थिति में है। चीन की विस्तारवादी गतिविधियां क्षेत्र में अशांति को ही जन्म दे रही हैं। सवाल है ऐसे तनावपूर्ण हालात में कैसे सीमा विवाद सुलझेगा और दो पड़ोसी देश कैसे शांति से रह पाएंगे?

सिद्धार्थ शंकर

कृषि कानूनों का भ्रम

प्रमोद भार्गव

तीन नए कृषि कानूनों के विरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा, 'जिनका इतिहास छल का रहा है, वे किसानों में नए कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं।' कृषि एवं किसान की हालत सुधारने वाले विधेयकों का विरोध व दुष्प्रचार समझ से परे है। दरअसल जब इन तीन विधेयकों को अध्यादेश के रूप में लाया गया था, तब संसद में लगभग सभी दलों ने स्वागत किया था। लेकिन अब, जब इन्हें कानूनी रूप देने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तब विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के भीतर ही घमासान हुआ। भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की सांसद और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तीनों विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्रीमण्डल से इस्तीफा दे दिया था।

आधुनिक खेती और अनाज उत्पादन का गढ़ माने जाने वाले हरियाणा-पंजाब में तभी से अन्नदाता आंदोलन पर उतारू हैं। पंजाब एवं हरियाणा की ग्राम पंचायतें फैसला ले रही हैं कि हर घर से एक व्यक्ति आंदोलन में भागीदारी करे। हरियाणा की 130 खाप पंचायतें भी इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन गई हैं। साफ है, सिंधु सीमा पर डेरा डाले किसान लंबी लड़ाई लड़ने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं।

अनुबंध खेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आशंकाएं बेबुनियाद हैं। दरअसल इन विधेयकों के माध्यम से सरकार भरोसा दे रही है कि किसान मंडियों, आढ़तियों और बिचौलियों से मुक्त हो जाएगा। औद्योगिक घरानों के पूंजी निवेश और तकनीकी समावेशन से पूरे देश में कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। फिलहाल देश में केवल हरियाणा-पंजाब में गेहूं की उत्पदकता 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो अंतरराष्ट्रीय कृषि उत्पादन दर से भी 13 प्रतिशत ज्यादा है। जबकि अन्य राज्यों में यही उत्पादकता आधी है। गोया, मंडियों का वर्चस्व खत्म कर अनुबंध-खेती लाभदायी होगी। किसानों को पूरे देश में फसल बेचने की छूट रहेगी। इससे किसान वहां अपनी फसल बेचेगा, जहां उसे दाम ज्यादा मिलेंगे। हालांकि पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, केरल और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकारों ने पहले से ही अनुबंध खेती की सुविधा दी हुई है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान कह रहे हैं कि किसान हित मंडी व्यवस्था के सुधार और एमएसपी को कानूनन अनिवार्य बनाने में सुरक्षित हो जाएंगे।

भारत सरकार ने बाधा मुक्त खेती-किसानी के लिए श्कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण और सुरक्षा) अनुबंध अध्यादेश-2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश-2020 विधेयकों को कानूनी दर्जा दिया है। अभीतक किसान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई मंडियों में ही उपज बेचने को बाध्यकारी थे। अब यह बाधा खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने बनारस की सभा में कहा कि, 'इसी के चलते किसान बनारस के लंगड़ा और दशहरी आम के साथ सब्जी, खाड़ी देशों से लेकर लंदन तक बेचने लगे।' किसानों को अनुबंध खेती की सुविधा दी गई है। किसान अब कृषि-व्यापार से जुड़ी कंपनियों व थोक-व्यापारियों के साथ अपनी उपज की बिक्री का करार खेत में फसल बोने से पहले ही कर सकते हैं। मसलन किसान अपने खेत को एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर देने को स्वतंत्र हैं। ये कानून किसान को फसल के इलेक्ट्रोनिक व्यापार की अनुमति भी देते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र के लोग, किसान उत्पादक संगठन या कृषि सहकारी समिति ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिससे इन प्लेटफार्मों पर हुए सौदे में किसानों को उसी दिन या तीन दिन के भीतर धनराशि का भुगतान प्राप्त हो जाए।

आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करके अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू आदि को इस कानून से मुक्त कर दिया है। नतीजतन व्यापारी इन कृषि उत्पादों का जितना चाहें उतना भंडारण कर सकेंगे। इस सिलसिले में किसानों को आशंका है कि व्यापारी उपज सस्ती दरों पर खरीदेंगे और फिर ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। हालांकि अभी भी व्यापारी इनका भंडारण करके नौकरशाही की मिलीभगत से कालाबाजारी करते हैं। इसे रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया है। लेकिन नौकरशाही इसे औजार बनाकर कदाचरण में लिप्त हो जाती है।

बावजूद किसान संगठन आशंका जता रहे हैं कि कानून के अस्तित्व में आने के बाद उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएगी। क्योंकि विधेयक में इस बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जबकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। मोदी के इस कथन को किसान जुबानी आश्वासन मान रहे हैं क्योंकि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी विधेयक नहीं देता है। अच्छा है, सरकार इस मुद्दे को विधेयक की इबारत में स्पष्ट कर दे। साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि व्यापारी एमएसपी दर से नीचे फसल नहीं खरीद सकें। ये शंकाएं दूर हो जाती हैं तो किसान निश्चिंत हो जाएगा।

विपक्ष का कहना है कि कंपनियां धीरे-धीरे मंडियों को अपने प्रभुत्व में ले लेंगी, नतीजतन मंडियों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी और किसान कंपनियों की गिरफ्त में आकर आर्थिक शोषण के लिए विवश हो जाएंगे। यह आशंका इसलिए बेबुनियाद है, क्योंकि राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। किसान को तो मंडी के अलावा फसल बेचने का एक नया रास्ता खुलेगा। साफ है, किसान अपनी मर्जी का मालिक बने रहने के साथ दलालों के जाल से मुक्त रहेगा। अपनी उपज को वह गांव में ही बेचने को स्वतंत्र रहेगा। अभीतक मंडी में फसल बेचने पर 8.5 फीसदी मंडी शुल्क लगता था, किंतु अब किसान सीधे व्यापारियों को फसल बेचता है तो उसे किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। नए कानून में तीन दिन के भीतर किसान को उपज का भुगतान करने की बाध्यकारी शर्त रखी गई है। साफ है, किसान को व्यापारी के धनराशि के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

नरेंद्र मोदी सरकार अस्तित्व में आने के बाद से ही खेती-किसानी के प्रति चिंतित रही है। इस नजरिए से अपने पहले कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की थी, इसी क्रम में 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण नीति' लाई गई थी। तब इस योजना को अमल में लाने के लिए अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके तहत दो हेक्टेयर या पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को हर साल तीन किश्तों में कुल 6000 रुपए देना शुरू किए गए थे। इसके दायरे में 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। जाहिर है, किसान की आमदनी दोगुनी करने का यह बेहतर उपाय है। यदि फसल बीमा का समय पर भुगतान, आसान कृषि ऋण और बिजली की उपलब्धता तय कर दी जाती है तो भविष्य में किसान की आमदनी दूनी होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ऐसा होता है तो किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों का पलायन रुकेगा और खेती 70 फीसदी ग्रामीण आबादी के रोजगार का जरिया बनी रहेगी। खेती घाटे का सौदा न रहे इस दृष्टि से कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशकों के मूल्य पर नियंत्रण भी जरूरी है।

केंद्र सरकार फिलहाल एमएसपी तय करने के तरीके में 'ए-2' फॉर्मूला अपनाती है। यानी फसल उपजाने की लागत में केवल बीज, खाद, सिंचाई और परिवार के श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है। इसके अनुसार जो लागत बैठती है, उसमें 50 फीसदी धनराशि जोड़कर समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है। जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि इस उत्पादन लागत में कृषि भूमि का किराया भी जोड़ा जाए। इसके बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि जोड़कर समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फसल का अंतरराष्ट्रीय भाव तय करने का मानक भी यही है। यदि भविष्य में ये मानक तय कर दिए जाते हैं तो किसान की खुशहाली बढ़ेगी। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष 2006 में यही युक्ति सुझाई थी। अब सरकार खेती-किसानी, डेयरी और मछली पालन से जुड़े लोगों के प्रति उदार दिखाई दे रही है, इससे लगता है कि भविष्य में किसानों को अपनी भूमि का किराया भी मिलने लग जाएगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

एड्स पीड़ितों के प्रति बेरुखी क्यों?

विश्व एड्स दिवस (01 दिसम्बर) पर विशेष

'एड्स' विश्व भर में आज भी एक भयावह शब्द है, जिसे सुनते ही भय के मारे पसीना छूटने लगता है। एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिन्ड्रोम) का अर्थ है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने से अप्राकृतिक रोगों के अनेक लक्षण प्रकट होना। एचआईवी संक्रमण के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की मामूली से मामूली बीमारियों का इलाज भी दूभर हो जाता है और रोगी मृत्यु की ओर चला जाता है। आज भी यह खतरनाक बीमारी दुनियाभर के करोड़ों लोगों के शरीर में पल रही है। एड्स महामारी के कारण अफ्रीका के तो कई गांव के गांव नष्ट हो चुके हैं। 'रॉयटर्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में एड्स महामारी शुरू होने के बाद से 77 मिलियन से भी अधिक लोगों में इसका वायरस फैल चुका है। वर्ष 2017 में विश्वभर में करीब 40 मिलियन लोग एचआईवी संक्रमित थे।

एड्स का इतिहास

अमेरिका में न्यूयार्क तथा कैलिफोर्निया में 1981 में जब न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, कपोसी सार्कोमा तथा चमड़ी रोग जैसी असाधारण बीमारी का इलाज करा रहे पांच समलैंगिक युवकों में एड्स के लक्षण पहली बार मिले थे। देखते ही देखते यह बीमारी तेजी से दुनिया भर में फैलने लगी तो हंगामा मच गया था। चूंकि जिस समय उन मरीजों में एड्स के लक्षण देखे गए थे, वे सभी समलैंगिक थे इसलिए उस समय इस बीमारी को समलैंगिकों की ही कोई गंभीर बीमारी मानकर इसे 'गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी' (ग्रिड) नाम दिया गया था। इन मरीजों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता असाधारण रूप से कम होती जा रही थी लेकिन कुछ समय पश्चात् जब दक्षिण अफ्रीका की कुछ महिलाओं और बच्चों में भी इस बीमारी के लक्षण देखे जाने लगे, तब जाकर यह धारणा समाप्त हुई कि यह बीमारी समलैंगिकों की बीमारी है। गहन अध्ययन के बाद पता चला कि यह बीमारी एक सूक्ष्म विषाणु के जरिए होती है, जो रक्त एवं यौन संबंधों के जरिये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। तत्पश्चात् इस बीमारी को एड्स नाम दिया गया, जो एचआईवी नामक वायरस द्वारा फैलती है। यह वायरस मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है और धीरे-धीरे ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यही स्थिति 'एड्स' कहलाती है।

भारत में 1986 में एड्स का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से बीते वर्षों में एड्स के ढेरों मामले सामने आए। अगर एड्स के कारणों पर नजर डालें तो मानव शरीर में एचआईवी का वायरस फैलने का मुख्य कारण हालांकि असुरक्षित सेक्स तथा अधिक पार्टनरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना है लेकिन कई बार कुछ अन्य कारण भी एचआईवी संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। शारीरिक संबंधों द्वारा 70-80 फीसदी, संक्रमित इंजेक्शन या सुईयों द्वारा 5-10 फीसदी, संक्रमित रक्त उत्पादों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के जरिये 3-5 फीसदी तथा गर्भवती मां के जरिये बच्चे को 5-10 फीसदी तक एचआईवी संक्रमण की आशंका रहती है।

एड्स पीड़ितों से भेदभाव

डब्ल्यूएचओ तथा भारत सरकार के सतत प्रयासों के चलते हालांकि एचआईवी संक्रमण तथा एड्स के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के अभियानों का कुछ असर दिखा है और संक्रमण दर घटी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2010 से अभीतक एचआईवी संक्रमण की दर में करीब 46 फीसदी की कमी आई है जबकि इस संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 22 फीसदी कम हुआ है। फिर भी भारत में एड्स के प्रसार के कारणों में आज भी सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता एवं जिम्मेदारी का अभाव, अशिक्षा, निर्धनता, अज्ञानता और बेरोजगारी प्रमुख कारण है। अधिकांशतः लोग एड्स के लक्षण उभरने पर भी बदनामी के डर से न केवल एचआईवी परीक्षण कराने से कतराते हैं बल्कि एचआईवी संक्रमित किसी व्यक्ति की पहचान होने पर उससे होने वाला व्यवहार बहुत चिंतनीय है। इस दिशा में लोगों में जागरुकता पैदा करने के संबंध में सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भले ही कितने भी दावे किए जाएं पर एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव के सामने आने वाले मामले, विभिन्न राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों एवं सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों की पोल खोलते नजर आते हैं।

अपने भी छोड़ जाते हैं साथ

पिछले साल एचआईवी संक्रमित बच्चों के लिए 'छत्तीसगढ़ नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स' नामक संस्था द्वारा उन बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा एचआईवी संक्रमित बच्चे और उनके अभिभावक शामिल हुए थे। कार्यक्रम में एड्स पीड़ितों को लेकर लोगों के नजरिये और समाज के रवैये के प्रति चिंता साफ देखने को मिली थी। एचआईवी संक्रमित कई ऐसे बच्चे थे, जिन्हें एड्स होने का पता चलते ही उनके रिश्तेदारों ने उनसे संबंध तोड़ दिए और पड़ोसियों ने दूरी बना ली। ऐसे बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को लोगों के ताने सुनने पड़े। ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों को अक्सर लोगों के भेदभाव का डर सताता है।

योगेश कुमार गोयल

सामाजिक जागरुकता की जरूरत

वास्तविकता यही है कि लोगों में एड्स के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए उस स्तर पर प्रयास नहीं हो रहे, जिस स्तर पर होने चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी भूमिका अभी भी सिर्फ चंद पोस्टर चिपकाने और टीवी चौनलों या पत्र-पत्रिकाओं में कुछ विज्ञापन प्रसारित-प्रकाशित कराने तक ही सीमित है। शायद यही कारण है कि 21वीं सदी में जी रहे भारत के बहुत से पिछड़े ग्रामीण अंचलों में खासतौर से महिलाओं ने तो एड्स नामक किसी शब्द के बारे में कभी सुना तक नहीं। तमाम प्रचार-प्रसार के बावजूद आज भी बहुत से लोग इसे छूआछूत की बीमारी ही मानते हैं और इसीलिए वे ऐसे रोगी के पास जाने से भी घबराते हैं। तमाम दावों के बावजूद आज भी समाज में एड्स रोगियों को बहुत सी जगहों पर तिरस्कृत नजरों से ही देखा जाता है।

एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरत है प्रत्येक गांव, शहर में इस संबंध में गोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनियां इत्यादि के आयोजनों की ताकि लोगों को सरल तरीकों से इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। एड्स जैसे विषयों पर सार्वजनिक चर्चा करने से बचने की प्रवृत्ति तथा एड्स पीड़ितों के प्रति बेरुखी व संवेदनहीनता की प्रवृत्ति अब हमें त्यागनी ही होगी। एड्स पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को सुरक्षित सेक्स एवं अन्य आवश्यक सावधानियों के लिए भी प्रेरित करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

लेखक- राकेश कुमार वर्मा

अपराधमुक्त राजनीति की पृष्ठभूमि

डटे हुए हैं राष्ट्रधर्म पर, विपदाओं में सीना ताने....कोरोनाकाल में बेरोजगारी और पलायन से उत्पन्न अर्थसंकट के बीच जहां मानवीयता के विविध आयाम देखने को मिले वहीं इसे कई लोगों ने कमाई का जरिया बनाया। इस संबंध में हाल ही में आई संसदीय समिति की रिपोर्ट में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को फायदा पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अदालत का समय बर्बाद करने का हवाला देते हुए उसे दण्डित करने का फरमान सुनाया। आज सत्ता में गौरवशाली प्राचीन परंपरा की भावनाओं को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि सत्तासीन है लेकिन राजनीति का हश्र यथावत है, केवल चेहरे बदल गये हैं परन्तु चरित्र नहीं बदला। यह दीगर बात है कि राजनीतिक स्वरूप बदल गया है। अब लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले पत्रकारिता का गुण-धर्म भी अवसरवाद में बदल गया है। वहीं सोशल मीडिया के दुरूपयोग से भीड़ हिंसा, फेक न्यूज, परस्पर वैमनस्यता से प्रेरित, परिणाम पूर्व निर्णायक खबरों के चलन ने जनहित के मुद्दों से जनहित कार्य से दूरी बना ली है। स्वस्थ्य सूचना के अभाव में लोगों की कार्यशैली प्रभावित हुई है, जिसने प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। जब हम किसी हिंसा पर पोषित होते हैं तो उसे विकृति कहते हैं, जब किसी को क्षति पहुंचाये बिना हम पोषण करते हैं तो वह प्रकृति कहलाती है किन्तु जब हम दूसरों के पोषण को प्राथमिकता देते हुए अपने पोषण की चिन्ता करते है तों उसे संस्कृति कहते हैं। इसी परंपरा को जीवंत रखने के लिए उत्सव मनाये जाते हैं। संस्कारों की बुनियाद पर परिष्कृत व्यक्तित्व का पथिक सत्ता के गलियारे से गुजरते ही मदमस्त हाथी के समान अपने ही बनाये मापदण्डों को रौंदता हुआ निकलता है। राष्ट्रवाद और राजनीति के चिंतक गोविन्दाचार्य की दृष्टि में ऐसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए समाज का अंकुश जरूरी है। शायद इसलिए उन्होंनें अटलजी को मुखौटा कहा था। शास्त्रों से राजनीति में आते-आते धर्म की व्याख्या बदल गई है। महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के रामराज्य की अवधारणा को अवसरवादिता के चश्मे से देखा जाने लगा है। इसके लिए चाहे करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपी भ्रष्ट नेता को सम्मानित करना पड़े अथवा 86 ग्राम गांजा रखने का अपराध घोषित कर किसी कलाकार को जेल भेजना पड़े। मौजूदा राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगो का प्रवेश एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका इलाज दूर-दूर तक नजर नहीं आता। इस मुद्दे पर कई वर्षों से चल रही बहस के बावजूद अपराधियों का राजनीति और सरकार में बढ़ते दुष्प्रभाव पर राजनीतिक विश्लेषक जनता को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति इन्हीं के वोट से चुनाव जीतकर सत्तासीन होता है। दरअसल जनता के समक्ष कई बार विचाराधारा और मुददों के आधार दुविधा का बड़ा करण होती है क्योंकि यदि वह मुददों के आधार पर सरकार हटाना या बनाना चाहती है तो वे उन स्थितियों में क्या करे जब उस पार्टी में कुशल नेतृत्व का अभाव हो। वहीं विचाराधारा आधारित स्थिति में ऐसे ही किसी उम्मीद्वार को वोट देना मजबूरी बन गई हो जो अक्षम हो। यह बात अलग है कि चुनाव जीतने या हारने पर भी लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों को अपेक्षतया सशक्त तरीके से उठाना चाहिये ताकि सत्ताधारी दल को उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य होना पड़े। गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आये चुनाव परिणाम के बाद वहां परस्पर विरोधी विचारधारा की सत्तासीन पार्टियों ने मतदाताओं के विश्वास को तोड़ा है। इस प्रसंग में चुनाव लड़ने और जीतने वाले नेताओं की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कर कई संस्थायें इस परिणाम पर पहुंची हैं कि समूची प्रवत्ति का राजनीति और जनता के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालतों ने भी अपने स्तर पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। बावजूद इसके आज भी अमूमन हर विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के आम चुनावों के बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि से औसतन निराशा हाथ लगती है। बिहार के प्ररिप्रेक्ष्य में हाल ही में आये एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 243 सदस्यों वाली विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित सदस्यों में से 142 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनमें से नब्बे यानि चालीस फीसदी सदस्यों पर हत्या, हत्या के प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अपहरण, और महिलाओं के खिलाफअपराध जैसे संगीन मामले दर्ज हैं । सत्तर विधायकों पर आरोप तय किए जा चुके हैं। ऐसे में राजनिति को दागियों से मुक्त करने की उम्मीद कोरी कल्पना प्रतीत होती है। ज्यादातर पार्टियों ने जिस तरह आपराधिक छवि के लोगों को अपना टिकट दिया है उससे स्पष्ट है कि उपरी तौर पर राजनीति के अपराधियों के दबंगई पर विरोध जताने वाले नेता और पार्टियां वास्तव में कितना उनके विरूद्ध हैं। सभी दल अपनी सुविधा के मुताबिक ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाती है जो राजनिति के अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इस प्रकार सत्तासीन नेताओं के जनहित से जुड़े कामकाज से लेकर अन्य गतिविधियों में ऐसे जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि राजनीति को दागदार करती है। ऐसे में चुनाव आयोग और मतदाता के साथ ही राजनीतिक दलों को तात्कालिक लाभ के मोह से मुक्त होकर समाजहित व राजनीति की दीर्घकालीन तस्वीर के बारे में सोचना चाहिए। अर्थव्यवस्था, गरीबी और कर निर्धारण पर यूपीए-नीति सरकार का विरोध जिस जयप्रकाश, लोहिया, अटल और कुशाभाऊ ठाकरे ने किया था आज उनकी ही सरकार के कार्यकाल में विकास के कई मानकों पर भारत को बांग्लादेश जैसे गरीब देशों से बदतर स्थिति में ला दिया है। ऐसे में भी निर्वाचन आयोग ने सांसदों और विधायकों के लिए चुनाव खर्च दस फीसदी बढ़ा दिया है। अर्थात् अब विधानसभा उम्मीद्वार 28 लाख की जगह 30 लाख 80 हजार तथा लोकसभा प्रत्याशी 70 लाख की जगह 77 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। कोरोना काल में जब जनता पर संक्रमण नियंत्रण के लिए शैक्षिक संस्थान, महिला और बाल विकास जैसे विभागों में व्यय की जाने वाली राशि नगण्य हो गई तथा सोशल डिस्टेंशिंग की अनिवार्यता लागू की गई हो तो ऐसे में माननीयों के सत्कार पर और भ्रमण पर होने वाले व्यय भी समाप्त होने चाहिये। महामारी के इस दौर में बदलते परिप्रेक्ष्य में नेताओं को देशभक्ति से जुड़कर सोचना चाहिये। बेहतर होगा यदि बिना वेतन और अन्य खर्च लिए बिना निस्वार्थ भाव से जनसेवा का वास्तविक पहचान बनकर एक ऐसी मिसाल पेश करें जिससे प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ सके। चुनाव खर्च में पारदर्शिता की अनिवार्यता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। दरअसल चुनावों में धनबल का प्रदर्शन अब खुले आम होने लगा है। शराब, साड़ी, गहने, नगदी, बर्तन आदि बांटने का चलन सा हो गया है। क्योंकि यह गुप्त तरीके से होता है अतएव आयोग उन खर्चों को चुनावी खर्च में जोड़ पाने में असमर्थ रहे हैं। वैसे भी दागी उम्मीद्वारों की तरह देश में बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है जिससे उनके लिए संविधान से अलग विशेष न्याय की व्यवस्था रही है। जब इस तरह से खर्च कर जनप्रतिनिधि सदन में पहुंचता है तो उसका संव्यवहार परिवर्तन स्वभाविक है, चाहे वह लोकहित में सदन में पूछे जाने वाले सवाल ही क्यों न हों?

काशी में देव दीपावली: 84 घाट, 15 लाख दीप

84 घाट, 15 लाख दीप और सौ टके की बात। बतौर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 23 वीं बार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में केवल देव दीपावली का ही दीप नहीं जलाया, उन्होंने विकास का भी दीप जलाया। आस्था का भी दीया जलाया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को उन्होंने जहां करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला।

काशी में देव दीपावली इस साल भी सोल्लास मनाई गई। काशी में गंगा के सभी 84 घाटों पर 15 लाख दीप जलाए गए। पहला दीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलाया। यह पहला अवसर है जब देव दीपावली पर किसी प्रधानमंत्री ने शिरकत की है और इतनी बड़ी तादाद में दीपक जलाए गए हैं। काशीवासियों का संकल्प था कि वे इसबार अयोध्या से भी भव्य दीपावली का आयोजन करेंगे और ऐसा हुआ भी। यूं तो काशी में शताब्दियों से देव दीपावली मनाई जा रही है लेकिन पिछले कुछ सालों से खासकर योगी आदित्यनाथ के शासन में काशीवासी अभूतपूर्व उत्साह के साथ देव दीपावली मना रहे हैं। अयोध्या में लंका विजय के बाद वहां के लोगों ने स्वतरू दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था लेकिन काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान की परंपरा स्वयं काशीपुराधिपति भगवान शिव के आदेश पर शुरू हुई।

काशी में देव दीपावली प्रतीक है त्रिपुरासुर पर भगवान शिव के विजय का। तैंतीस कोटि देवता आज काशी में आते हैं और भगवान शिव तथा मां गंगा की पूजा करते और दिवाली मनाते हैं। पुराणों में कथा आती है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। उसके बाद उन्होंने इस तिथि को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यही वजह है कि हर वर्ष देवता गण काशी में आकर देव दीपावली मनाने लगे। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गंगा या किसी पवित्र नदी के पास पूर्णिमा की रात्रि में दीप जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर जलाए गए दीपक के प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। ब्रह्माजी का अवतरण भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था।

भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी-देवता ने पूर्णिमा को लक्ष्मी-नारायण की महाआरती की थी। वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का ही था। कार्तिक माह भगवान कार्तिकेय द्वारा की गई साधना का माह है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रीकेशव के निकट अखण्ड दीपदान करता है, वह दिव्य कान्ति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्रीहरि के मन्दिर में रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता है। काशी और गंगा के तो दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है।

प्रधानमंत्री ने नये कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच उपजी आशंकाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया। वहीं विपक्ष के छल और अपनी गंगाजल जैसी नीयत का इजहार कर उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नई बहस का सूत्रपात भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गंगाजल जैसी पवित्र नीयत से काम कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम आने शुरू हो गये हैं और किसी को भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र के मिर्जामुराद के खजुरी में 2,447 करोड़ रुपये की हंडिया-राजातालाब राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ दशकों से छल किया जा रहा था। पिछली सरकारों के कार्यकाल में किसानों को तरह-तरह के धोखे दिये जा रहे थे। कभी फसलों के न्यूनतम मूल्य दिलाने के नाम पर तो कभी सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर और कभी किसानों के बकाया ऋण माफ करने के नाम पर। इन सबका लाभ कभी किसानों को नहीं मिल पाता था। इसलिए उनकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। नये कानून से किसानों को लाभ मिलने शुरू हो गये हैं। आने वाले समय में देश के सभी छोटे-बड़े किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा लेकिन जो लोग किसानों के साथ छल करते रहे, अब वे निरंतर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जिससे सावधान रहने की जरूरत है।

सियाराम पांड्ेय 'शांत'

नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों को अगर कोई शंका है तो सरकार उसे लगातार दूर कर रही है तथा इस प्रकार के प्रयास आगे जारी रहेंगे। अपने 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 26 मिनट तक किसानों के मुद्दे पर ही बात की। वाराणसी के दशहरी और लंगड़ा आम की तारीफ करना भी वे नहीं भूले। उन्होंने किसानों को लगे हाथों यह बताने की भी कोशिश की कि अगर वे पुराने सिस्टम से ही लेनदेन को ठीक समझते हैं तो उनपर भी कहीं कोई रोक नहीं लगी है। नया कानून उनके लिए फायदेमंद है। इसमें उन्हें और आजादी दी गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूर्व की सरकारों ने कितनी खरीदारी की और भाजपा सरकार ने कितनी खरीदारी की। यह भी समझाया कि अगर मंडियों को ही खत्म करना होता तो वे उन्हें इतना मजबूत क्यों बनाते। उनकी योजनाओं तो मंडियों को और अधिक अत्याधुनिक बनाने की है।

न्यूज ब्रीफ

5 दिनों तक सीसीआई नहीं करेगा कपास की खरीदी

माही की गूंज, खरगोन। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीदी की मात्रा अत्यधिक होने से जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास का अधिक स्टॉक हो गया है, इसलिए वह 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक कपास की खरीदी नहीं करेगा। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि, सीसीआई द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि, आनंद नगर स्थित कपास मंडी प्रांगण से 5 दिनों तक कपास की खरीदी नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री आज 5 लाख किसानों के खाते में भेजेंगे 100 करोड़

माही की गूंज, बड़वानी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के नसरुल्लागंज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान, प्रदेश के 5 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 100 करोड रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन भेजेंगे। इस दौरान जिले के कुछ किसानों को प्रतीकात्मक रूप से संबंधित राशि के चेक की छाया प्रति भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा वितरित की जाएगी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार आज दोपहर साढे 12 बजे से सीहोर से नसरुल्लागंज में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़वानी जिले के 6 हजार 296 किसानों के खाते में भी 1 करोड़ 25 लाख 96 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय के महाविद्यालय के सभागृह में दिखाने की व्यवस्था भी की गई है।

जिले से पांच आरोपी जिला बदर

माही की गूंज, बड़वानी। जिला दंडाधिकारी बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सेंधवा निवासी सोनू उर्फनिलेश पिता उमेश कोली (19) को एवं सेंधवा निवासी साकिर पिता जाकिर अली (27) को एक वर्ष के लिए, सेंधवा निवासी अशोक पिता माहरू मोरे (39) एवं राजपुर निवासी सचिन पिता कैलाशचन्द्र भाटी को 6 माह के लिए, ग्राम मोगरीखेड़ा निवासी मनीष पिता सोहल्या बारेला (30) को 3 माह के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बदर हुए उक्त आरोपियों को बड़वानी जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा। वही वे जिला बदर किए गए निर्धारित अवधि में बड़वानी सहित सीमावर्ती जिले धार, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर की राजस्व सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम 12 दिसंबर को

माही की गूंज, खरगोन। समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम अब 12 दिसंबर को आयोजित होगी। पहले यह कार्यक्रम 1 दिसंबर को आयोजित होना था, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान चीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं के आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे। इस कार्यक्रम में संबंल योजना के तहत प्रसूति सहायता के वितरण, खाद्यान्न पर्ची वितरण, कर्मकार मंडल संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विद्युत ट्रांसफर्मर बदलने संबंधी प्रकरणों, मनरेगा योजना में लंबित मजदूरी के भुगतान तथा नगरीय निकायों में सड़क सुधार से संबंधित आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाएगी।

महिष्मति कला मंच की काव्य गोष्ठी संपन्न, साहित्यकारों की रचनाओं और कविताओं ने जमकर बटोरी दाद

नव मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर अभिनंदन किया गया

माही की गूंज, झाबुआ।

महिष्मति कला मंच की आवश्यक बैठक तथा काव्य गोष्ठी का आयोजन रविवार को सिद्धेश्वर कॉलोनी स्थित रोटरी सदन में हुआ। यह कार्यक्रम तीन चरणों में हुआ। प्रथम चरण में महिष्मति कला मंच के नव-मनोनीत पदाधिकारी-सदस्यों को नियुक्ति पत्र देकर स्वागत किया गया। दूसरे चरण में जिला पंचायत से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. वाहिद शेख 'पराज' का संस्था की ओर से भावभरा सम्मान किया गया। अंतिम चरण में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों और कवियों ने अपनी-अपनी रचनाओं और कविताओं के माध्यम से जमकबर वाहवाही और दाद बटोरी।

कार्यक्रम महिष्मति कला मंच के संस्थापक नरेन्द्र 'अटल' के मार्गदर्शन में रखा गया। शुभारंभ कला मंच के क्षेत्रीय प्रभारी यशवंत भंडारी, जिलाध्यक्ष एमएल फुलपगारे, पीडी रायपुरिया तथा डॉ. जयनारायण बैरागी आदि ने शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। जिसके बाद युवा कवि दर्शन कहार ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। पहले चरण में कला मंच की जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सर्वानुमति से जिला उपाध्यक्ष मंगला गरवाल तथा सुभाष अंगारा रानापुर, सचिव महेन्द्रकुमार खुराना तथा मनोज परमार, कोषाध्यक्ष दर्शन कहार, जिला संयोजक पीडी रायपुरिया, जिला मीडिया प्रभारी दौलत गोलानी को बनाया गया। जिला कार्यसमिति सदस्य में दिनेश पंड्या सिंदुर, अंबरीश भावसार, संजय कानूनगो, गौरी कटारा तथा मुख्य संरक्षक सुरेश सत्रावा को मनोनीत किया गया। सभी नव-मनोनीत पदाधिकारी-सदस्यों की घोषणा तथा संकल्प संस्था के जिलाध्यक्ष फुलपगारे ने दिलवाया। सभी पदाधिकारी-सदस्यों का पुष्पमाला पहनाकर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

काव्य पाठ और रचनाओं से किया सभी को ओत.प्रोत

तीसरे चरण में आयोजित काव्य गोष्ठी में वरिष्ठ साहित्यकार पीडी रायपुरिया, एमएल फुलपगारे, प्रदीपकुमार अरोरा, मंगला गरवाल, डॉ. जयनारायण बैरागी, महेन्द्रकुमार खुराना, संजय कानूनगो, प्रदीप ओएल जैन आदि ने अपनी ओजस्वी और तेजस्वी रचनाओं तथा कविताओं से सभी ओत-प्रोत किया। कार्यक्रम का संचालन महिष्मति कला के जिला महासचिव प्रवीण सोनी ने किया तथा अंत में आभार भैरूसिंह सोलंकी ने माना। इस अवसर

- माहिष्मति कला मंच के सभी नव-मनोनीत पदाधिकारियों के स्वागत के साथ सम्मान किया गया।

पर तय किया गया कि माहिष्मति कला मंच द्वारा प्रति माह में दो बार पाथिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कला मंच से जुड़े साहित्यकार, कवियों के साथ जिले के सभी साहित्यकार-मनीषियों से भी सहभागिता कर स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाओं, कविता और काव्यों का पाठ करने हेतु आमंत्रित किया गया है।

जिले में यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता - उप संचालक कृषि

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही रबी फसलों के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान मौसम में रबी फसलों हेतु 1 लाख 3 हजार 985 हेक्टर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 84 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र में गेहूं तथा 8 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र में चना फसल की बोनी की जाना प्रस्तावित है। रबी की इन फसलो के लिए किसान भाईयों को उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था करवाई गई है। विशेषकर विगत वर्षों में यूरिया की कमी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त यूरिया भंडारण के प्रयास किए गए है।

उप संचालक कृषि केएस खपेड़िया ने बताया कि, जिले में रबी फसलों के लिए 28 हजार मेट्रिक टन यूरिया वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध आज तक जिले में 11 हजार 400 मैट्रिक टन प्राप्त होकर जिले के किसानों को 6 हजार 400 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है तथा 5 हजार मैट्रिक टन शेष है। जिले में शेष यूरिया भंडारण की प्रक्रिया निरंतर जारी है तथा किसान भाईयों को रबी मौसम के हर अंतराल में उनकी मांग अनुसार यूरिया की उपलब्धता के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों के नियमित सदस्यों को संबंधित समितियों द्वारा परमीट पर नियमित रूप से यूरिया वितरित किया जा रहा है। जो किसान समिति के डिफाल्टर हैं वे समिति में मात्र खाद की बकाया राशि जमा कर भी संस्था से खाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान बकाया राशि जमा करने में असमर्थ है तो विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों से ऐसे किसानों को नगद पर खाद प्रदाय की सुविधा प्रदान की गई है।

चलित प्रयोगशाला ने जांची खाद्य पदार्थों की शुद्धता

जांच में पाया तेल का उपयोग तीन से अधिक बार किया गया

माही की गूंज, खरगोन। खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच और मिलावट की जागरूकता की दिशा में शासन द्वारा नवकरणीय पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल के तहत् मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत इंदौर संभाग में चलाए जा रहे चलित जांच प्रयोगशाला बुधवार को सेगांव पहुंचा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि, सेगांव के विभिन्न प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों की जांच करने के बाद खरगोन पहुंचा। खरगोन स्थित बस स्टैंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच की गई। चलित प्रयोगशाला के पहले दिन कुल 37 नमूनों की शुद्धता जांच की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि, चलित प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों की शुद्धता की तत्काल जानकारी मिलती है। चलित प्रयोगशाला के संबंध में इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा को रिपोर्ट भेजी जाएगी। चलित प्रयोगशाला गुरुवार को गोगावां होते हुए सनावद नगर पहुंचेगी और खाद्य पदार्थों की जांच करेगी।

खरगोन के बस स्टैंड स्थित नटराज होटल से चलित प्रयोगशाला द्वारा तेल की नमूने की जांच की गई, जांच में खाद्य तेल अशुद्ध पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि, लिए गए सैंपल में तेल का तीन बार से अधिक उपयोग किया जाना पाया गया है। अशुद्ध पाए जाने पर मौके से 24 लीटर तेल नष्ट किया गया। चलित प्रयोगशाला द्वारा पहले दिन सेगांव में 17 और खरगोन में समाचार लिखे जाने तक 20 सैंपल जांचे गए। खरगोन में अंकिका, मिलन, शुभम होटल, सांवरिया स्वीट और हरिओम किराणा दुकान आदि से सैंपल लिए गए। खरगोन में मिठई, मावा, दही, रबड़ी, जलेबी, इमरती, दुध, नमक, चाय, नमकीन, हल्दी, धनिया व मिर्च तक के कुल 37 नमूनों की जांच की गई।

बाल विवाह करने पर होगी कार्रवाई

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने जिले में बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए है। बाल विवाह करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में कही भी बाल विवाह हो तो आम नागरिक बाल विवाह की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, महिला हेल्पलाइन नम्बर 181 पर सम्पर्क कर सकते है।

बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी प्रभावी है। इस अधिनियम अंतर्गत कोई भी बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष से कम एवं बालक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है विवाह बाल विवाह कहलायेगा। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाल विवाह किए जाने पर बच्चों के माता-पिता, विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदार सेवा प्रदाता जैसे प्रिंटिंग प्रेस, बैंड वाले, हलवाई, गार्डन/धर्मशाला मालिक, घोड़ी वाले आदि सभी को भी बाल विवाह में सहयोगी मान कर, आरोपी माना जाएगा, ऐसे विवाह (बाल विवाह) में इस प्रकार से सहयोग किया जाने पर 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

विश्व एड्स दिवस पर किया जागरूक

माही की गूंज, बड़वानी।

सत्य साई मेडिकल कॉलेज बड़वानी एवं नेहरू युवा केन्द्र बड़वानी के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया। जिसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढाना, है। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और दुनिया भर में लोग अक्सर एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ, इस दिन का निरीक्षण करते हैं। डरना नहीं समझना होगा तभी एड्स जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केन्द्र के जिला समन्वयक नीतीश कुमार सोनी तथा शिवानी चोयल ने डॉ राजेश जायसवाल, डॉ अजय कमले, डॉ शोभाराम कमले, माया मेहता आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्र किसानों का सत्यापन किया जाए

दुकानदारों द्वारा कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा पात्र सभी किसानों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर रोहित सिंह ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। सिंह ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के सत्यापन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले में इस योजना के तहत लगभग 1 लाख 12 हजार किसानों का सत्यापन करने का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 1 लाख किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। कलेक्टर सिंह ने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के मैदानी अधिकारियों की एक सयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को स्वीकृत कराकर राशि का वितरण सुनिश्चित कराए। इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में इस जिले को अग्रणी लाने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।

कलेक्टर सिंह ने जिले में बिजली आपूर्ति के कार्य की समीक्षा की और अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देश दिए हैं कि जिले में ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल बदलने की कार्यवाही करें ताकि विद्युत प्रदाय व्यवस्था में व्यवधान पैदा न हो। इस बैठक में रासायनिक ऊर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा की गई और कृषि विभाग के जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में पर्याप्त मात्रा में ऊर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को आवश्यकतानुसार ऊर्वरक उपलब्ध हो सके। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आंवटित कलस्टर के ग्रामों का सघन भ्रमण कर कार्ड बनाने के कार्य में गति लाए। साथ ही घर-घर जाकर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाए। इसी प्रकार आधार कार्ड बनाने के लिए कैम्प आयोजित किए जाए।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि सौंपे गए कार्य बेहतर ढंग से सम्पादित किए जा सके। इस महामारी की रोकथाम तथा बचाव के लिए शासन के दिशा-निर्देशों और गाईड लाईन का कड़ाई से पालन हो। साथ ही दुकानदारों द्वारा पहली बार कोविड-19 के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 500 रूपए, द्वितीय बार 1000 रूपए तथा तीसरी बार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकान बंद करने की कार्यवाही करें।

जनपद स्तर पर होगी जनसुनवाई

सिंह ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए हैं कि इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि इसके अच्छे परिणाम आ सके। उन्होने जिले में अवैध शराब तथा अवैध रेत परिवहन की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की और आबकारी तथा खनिज विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने जनपद पंचायत स्तर पर जन सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में अवैध कालोनियों की जांच करें और जांच में अनियमितांए पाई जाने पर संबंधित तहसीलदार की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही करें। इस बैठक में समयावधि के लंबित पत्रों, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई और उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अपर कलेक्टर जेएस बघेल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एमएलमालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला अनिल भाना, डिप्टी कलेक्टर डॉ. अभयसिंह खरादी, डिप्टी कलेक्टर ज्योति परते सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

- कलेक्टरेट सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई

औद्योगिक क्षेत्रों से हटाया अतिक्रमण

माही की गूंज, खरगोन।

औद्योगिक क्षेत्र औरंगपुरा और भाडली में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा बुधवार को की गई। एसडीएम सत्येंद्रसिंह ने बताया कि, 19 नवंबर को जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र और भाडली में अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने राजस्व, उद्योग व श्रम विभाग के अधिकारियों का दल बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। एसडीएम श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, औरंगपुरा से 6 दुकानें और 1 गोदाम तथा भाडली क्षेत्र में 2 अवैध मकानों का अतिक्रमण हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार आरसी खतेड़िया, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले व उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक श्रीमती चंचल अग्रवाल उपस्थित रही।

शहर में लावारिस घूम रही गायों को भेजा गया शासकीय गौशाला

माही की गूंज, बड़वानी।

नगर में लावारिस एवं सड़कों पर इधर-उधर घूम रही गायों को नगर के अमले ने पकड़ कर शासकीय गौशाला तलवाड़ा बुजुर्ग पहुंचाया। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि, नगर में यह अभियान उस समय तक जारी रहेगा जब तक सभी लावारिस गायों को शासकीय गौशाला नहीं पहुंचा दिया जाता।

नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डोडवे से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर में विगत 2 दिनों से प्रारंभ इस अभियान के दौरान लगभग 40 गायों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाया गया था। वहां से इन गायों को किसी के द्वारा नहीं छुड़ाने पर इन्हें शासकीय गौशाला तलवाड़ा बुजुर्ग पहुंचाया गया है, जिससे इनके खाने-पीने की उचित व्यवस्था एवं देखभाल की जा सके।

डोडवे ने बताया कि, लावारिस पशुओं को रात्रि के दौरान विभिन्न चौराहों पर बैठ जाने के दौरान अकसर दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी, जिसके कारण बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए इन पशुओं को पकड़कर शासकीय गौशाला पहुंचाया गया है। उन्होंने समस्त पशु पालकों से अनुरोध किया है कि, वे अपने पालतू पशुओं को बांध कर रखें। जिससे वे सड़कों पर स्वच्छंद विचरण ना करने पाए।

लेखापाल जोशी की जनसुनवाई में शिकायत के सोलह माह बाद भी कार्रवाई का इंतजार

मामला फर्जी वेतन भुगतान का...

जिला कलेक्टर रोहित सिंह के सामने शिकायतकर्ता ने फिर लगाई गुहार

माही की गूंज, पेटलावद।

खण्ड शिक्षा कार्यालय पेटलावद में पदस्थ लेखापाल उमेन्द्र जोशी पर बिना कार्य किए फर्जी वेतन भुगतान कर वित्तीय अनियमित्ता की शिकायत के सोलह माह बाद भी कलेक्टर झाबुआ द्वारा शासन हित मे कार्रवाई नही की गई। शिकायतकर्ता रमेश धानूक द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित होकर 30 जुलाई 2019 को शिकायत दर्ज करवाई थी जहां से शिकायत क्रमांक 48788 दिया गया था, शिकायत के साथ वित्तिय अनियमित्ता के प्रमाणित दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए गए थे। गूंज द्वारा पूर्व में ही खुलासा मय प्रमाण के किया जा चुका है कि, कैसे लेखापाल उमेन्द्र जोशी द्वारा बिना प्राचार्य के उपस्थिती पत्रक और वेतन पत्रक नही देने के बाद भी जोशी ने अपने हस्तलिपि से गोपनीय तरीके से अलग-अलग बिल के माध्यम से एक वर्ष का वेतन भुगतान कर भारी वित्तीय अनियमित्ता की थी।

कार्रवाई के नाम पर किया गया गुमराह

जनसुनवाई में शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, विभाग ने बड़ी सफाई से गुमराह करते हुए जनसुनवाई पोर्टल पर जांच प्रतिवेदन में पाई गई कमियों के चलते संबधित लेखा लिपिक के विरुद्ध विभागीय रूप से अनुशात्मक कार्यवाही के लिए रामचंद्र अटकान को आरोप आधार पत्र जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है और संबधित प्राचार्य कन्या उमावि पेटलावद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल होने से उनके विरुद्ध अनुशात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित किए जा रहे है, जबकि नामजद शिकायत लेखापाल उमेन्द्र जोशी के विरुद्ध न तो कोई जांच करवाई गई न ही कोई कार्रवाई विभाग की और से की गई ये विचारणीय है।

कलेक्टर रोहितसिंह को फिर लगाई गुहार

पूर्व कलेक्टर प्रबल सिपाहा द्वारा जांच के नाम पर मामला दबाने और शिकायत का कोई निराकरण नही होने पर शिकायतकर्ता रमेश धानूक ने 9 नवम्बर को झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह को आवेदन पेश कर पिछले 16 माह से अटकी पड़ी शिकायत का निराकरण करने की मांग की है। जिला कलेक्टर रोहित सिंह की कार्यशैली और शिकायतो पर की जा रही कार्यवाही को देखते हुए शिकायतकर्ता रमेश धानूक को लेखापाल जोशी पर कार्रवाई की उम्मीद है।

उपादान राशि भुगतान में रिश्वत लेने की भी चल रही है जांच

खण्ड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ जोशी विगत 27 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ होकर लगातार भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे है, फर्जी वेतन भुगतान हो या 20 लाख के फर्जी मजदूरी भुगतान का मामला जोशी हर बार अपनी अधिकारियों की जुगबन्दी से बचने में कामयाब हो जाता है। अभी वर्तमान में भी रिटायर्ड रसोयन कर्मचारी की उपादान राशि के भुगतान के मामले में लेखापाल उमेन्द्र जोशी पर राशि के भुगतान के लिए दस हजार की रिश्वत लेने की शिकायत की गई है, जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद द्वारा की जा रही है। उक्त मामले में भी जोशी अपने पासे बिठाकर अधिकारी को गुमराह कर एक अन्य शिक्षक को फसाकर बचने की फिराक है जबकि शिकायतकर्ता ने सीधे-सीधे लेखापाल उमेन्द्र जोशी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

विश्व एड्स दिवस पर जिला जेल में बंदियों को किया जागरूक

माही की गूंज, अलीराजपुर।

1 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर जीवन ज्योति हेल्थ सर्विस टी.आई. परियोजना द्वारा जिला चिकित्सालय में जाकर नोडल अधिकारी सन्तोष सोंलकी, डॉ.वंदना ढोके व सभी नर्स स्टाफको रेड रिबिन लगाए गए।

जिला अपर न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला जेल परिसर में एचआईवी एड्स पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जेल परिसर में जिला जेल अधीक्षक जे.एस. बाथम एवं जेल स्टाफको रेड रिबन लगाया गया कार्यक्रम में परियोजना प्रबन्धक हितेश जोशी द्वारा रेड रिबन, विश्व एड्स दिवस व मुख्य एचआईवी व एड्स पर प्रकाश डाला गया एवं यौन रोगों एवं उसके संचरन पर मार्गदर्शन में कोविड -19 की गाइडलाईन का पालन करते हुए रेड रिबन कैंपेन संपन्न किया गया। साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी सिमोन सुलिया द्वारा उच्च जोखिम समुह के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता हेतु व अन्य किसी भी विधिक सहायता के लिए आश्वस्त किया गया।

प्रोग्राम मैनेजर हितेश जोशी ने बंदियों और हवालातियों को बताया कि, हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। श्री जोशी ने बताया कि, एड्स एक ला-इलाज और भयंकर बीमारी है, इसका एक ही इलाज है सावधानी।

प्रीति पंवार ने जिला जेल में महिलाओं को बताया कि, एचआईवी के प्रति लोगों में जागरूकता अवश्यक है लोगों को एचआईवी मरीज से परहेज नहीं करना चाहिए एड्स छूने से नहीं बल्कि संक्रमित सुई एवं सिरिंज तथा संक्रमित व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिए गए रक्त से इसके फैलने की संभावना होती है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। एड्स नियंत्रण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, इसके लिए सुरक्षा को ही सबसे बड़ा बचाव बताया गया।

'फिट इण्डिया प्रभात फेरी 2020' 04 दिसम्बर को

माही की गूंज, झाबुआ।

शारीरिक गतिविधि तथा खेलकूद को नागरिकों के दैनिक जीवन का एक अंग बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों में स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा फिट इण्डिया कैम्पेनिंग दिसम्बर 2020 - 'फिटनेस का डोज-आधा घंटा रोज' के अन्तर्गत जिला मुख्यालय झाबुआ में फिट इण्डिया प्रभात फेरी का आयोजन 04 दिसम्बर को सुबह 07 बजे से बस स्टैण्ड से किया जा रहा हैं। प्रभात फेरी बस स्टैण्ड से प्रारम्भ होकर थान्दला गेट, आजाद चौक, राजवाड़ा चौक, बुनियादी शाला, उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान झाबुआ पर सम्पन्न होगी।

'फिट इण्डिया प्रभात फेरी 2020' में किसी भी आयु वर्ग का स्वस्थ्य व्यक्ति भाग ले सकता हैं। प्रभात फैरी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मास्क लगाना अनिवार्य हैं तथा प्रभात फेरी में शामिल प्रतिभागियों के द्वारा शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। भाग लेने वाले प्रतिभागियों को फिट इण्डिया की ओर से ई-सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, ई-सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रतिभागियों को प्रभातफेरी उपरान्त संपूर्ण ब्यौरे को फिट इंडिया वेबसाइट में व्यक्तिगत प्रोफाइल में अपलोड करना होगा। फिट इंडिया प्रभातफेरी 2020 के ई-सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी को अपनी प्रभातफेरी का ब्यौरा फिट इण्डिया वेबसाईट पर अपलोड करना होगा व इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी को रजिस्टेशन स्वयं करना होगा।

राज्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की कि समीक्षा

माही की गूंज, शाजापुर। सभी निर्माण विभाग सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा निर्मित की जा रही संरचना जैसे कि भवन, सड़क, तालाब, बैराज, जलाशय आदि उत्तम गुणवत्तायुक्त हो। उक्त निर्देश प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने जिला मुख्यालय पर सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर कलेक्टर दिनेश जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसएल सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी यूयू भिड़े, पूर्व मंडी अध्यक्ष शुजालपुर कैलाश सोनी सहित विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी मौजूद थे। राज्यमंत्री श्री परमार ने कहा कि, भवन निर्माण के पश्चात आमतोर पर छत टपकने की सबसे ज्यादा शिकायत मिलती है, उन्होंने निर्देश दिए कि, सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण के दौरान ही छत की गुणवत्ता का ध्यान रखें। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री श्री परमार ने कहा कि, शुजालपुर के चिकित्सालय की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाए। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण रविन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि, जिले में 129 करोड़ 87 लाख 58 हजार के 24 कार्य स्वीकृत हैं, इससे 143.90 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा।

पीआईयू संभागीय परियोजना यंत्री राजेश रायकवार ने बताया कि, जिले में उच्च शिक्षा, आयुष, महिला एवं बाल विकास, लोक शिक्षण, राजस्व एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबंधी कुल 28 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनकी प्रशासकीय लागत 66 करोड़ 4 लाख रूपए है। पीआईयू के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री परमार ने लोक शिक्षण विभाग के कार्यों को प्राथमिकता के साथ मार्च 2021 के पूर्व पूर्ण करने के लिए कहा, ताकि नए सत्र में बच्चे नए विद्यालय में अध्ययन कर सकें। तहसील भवन के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय एक सभा कक्ष के निर्माण को भी रखें, जिसमें कम से कम 100 लोगों की एक साथ बैठक ली जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग मद से निर्मित होने वाले आवासीय भवनों को भी उपयोगितानुसार डिजाइन कर प्रस्ताव बनाए।

जलसंसाधन कार्यपालन यंत्री पीसी सांकला ने बताया कि, जिले में 2 मध्यम परियोजनाएं एवं 88 लघु सिंचाई योजनाएं संचालित है, इससे 31 हजार 975 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य हो रहा है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि, जिले में सालिया, ढाबलाधीर एवं मुरादपुरा, लोंदिया बेराज की योजनाओं की साध्यता दर्ज की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 27 करोड़ 96 लाख 50 हजार रूपये है, इससे 1655 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि, अनुसूचित जाति विभाग के 50 शैया वाले 3 छात्रावासो का निर्माण किया जाना है।

विश्व एड्स दिवस पर वेबिनार का हुआ आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में विश्व एड्स दिवस पर महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाईन वेबिनार का आयोजन किया। जिसके मुख्य वक्ता के रूप में राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा एड्स जन-जागरूकता विषय पर अपना उद्बोधन दिया। जिसमें विधि आधारित एड्स से पीड़ित व्यक्ति को निरूशुल्क सहायता, सम्पत्ति पर क्लेम होने की स्थिति में विधिक सहायता दी जाती है । इसी के साथ एचआईवी के संक्रमण तथा बचाव व एड्स बीमारी में जन-चेतना तथा जन-जागरूकता के संबंध में विस्तृत व्याख्यान दिया।

रेड रिबन क्लब व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में एड्स जागरूकता अभियान के अंतर्गत ऑनलाईन निबंध, पोस्टर निर्माण तथा स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व जिला संगठक डॉ. गीता दुबे ने मुख्य वक्ता राजेश देवलिया का स्वागत करते हुए एड्स पर उद्बोधन देते हुए युवाओं को जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राजू बघेल ने कार्यक्रम का संचालन किया। आभार एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रो. मनीषा सिसोदिया ने माना।

तिहरे मर्डर काण्ड के साथ अन्य हत्या का भी पुलिस ने किया खुलासा

लूट को अंजाम देने के लिए गुजरात के साइको किलर ने साथियों के साथ मिलकर दिया अंजाम, चार आरोपी गिरफ्तार, मुख्य एक फरार

माही की गूंज, रतलाम। राघवेंद्र सिंह डोडिया

थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में 25-26 नवम्बर की रात राजीव नगर के निवासी गोविंद पिता बगदीराम सोलकी, शारदा बाई व उनकी बेटी दिव्या की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले को माही की गूंज ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अग्यात आरोपियो कि तलाश में जुट गई। रतलाम रेज की पुलिस व पुलिस अधिक्षक, एफएसएल अधिकारी, सायबर सेल, फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट आदि घटनास्थल पर पहुंच कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की तसीश के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी आदि के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। जिसमे पुलिस ने आसपास रहने वाले निवासियो के कथन लिए, साथ ही सीसीटीवी कैमरो को खंगाला गया व सायबर सेल की मदद ली गई।

हत्या कर स्कूटी से फरार हुए थे हत्यारे

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से ज्ञात हुआ कि, मकान गोविंद सोलंकी का ही है और उनके मकान में किराएदार लोग रहते है। किराएदार ने सूचना दि कि, स्कूटी घर के नीचे से गायब है। जिसकी जांच की तो पता चला कि, मृतिका दिव्या की स्कूटी की चाबी गायब है ओर किराएदार की स्कुटी घटनास्थल से गायब है। पुलिस ने इसकी तलाश कर टोल नाके आदि से जानकारी निकाली गई। उक्त स्कूटी 26 नवम्बर की शाम को देवरा देवनारायण कालोनी में स्थित मंदिर के पास मे लावारिस हालत में मिली। स्कूटी कैसे पहुंची आदि की जानकारी निकालते हुए सीसीटीवी कैमरे आदि के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि, दो लोग जो कि अलग-अलग स्कूटी पर आए थे, उनमें एक ने स्कूटी वहां छोडकर दूसरी स्कूटी के पीछे बैठकर वहां से भागे। तसीश में घटना कि रात में ही घटनास्थल से आरोपियों के भागने के रूट को ट्रेक किया गया ओर सायबर सेल की टीम भी लगाई गई। 200 से अधिक स्थानो पर लगे सीसीटीवी कैमरे आदि को खंगाला गया।

खुले ग्राउंड में मिलकर तैयार की रूपरेखा

पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि, घटना को अंजाम देने के लिए घटना कर भागने के रूट आदि की रैकी करते रहे। इसके बाद लगभग रात 8 से सवा 8 बजे के आस-पास आरोपी खुले ग्राउण्ड मे एकत्रित होकर रूपरेखा तैयार की और घटना को अंजाम देने के लिए चार लोग शामिल थे जिसमें मुख्य मास्टर माईन्ड दिलीप देवल जो दाहोद का रहने वाला है। दिलिप अपने साथ में बॉबी उर्फ अनुराग तथा गोलू उर्फ गौरव बिलवाल, निवासी रतलाम, लाला भाबोर निवासी दाहोद, इन लोगो ने घटना को अंजाम देने के लिए 23 नवम्बर को ही योजना बना ली थी। योजना अनुसार छोटी दिपावली (देव उठनी ग्यारस) को चुना ताकी उस दिन आतिशबाजी आदि होने से फायरिंग आदि के दौरान लोगों को पता नहीं चले। मौका देख दिलीप, अनुराग उर्फबॉबी व लाला भाबोर घर के अंदर घुसे व चौथा साथी गोलू उर्फगौरव इसको बाहर मोटर सायकल व स्कूटी की निगरानी करने एवं गाडी चालू रखने के लिए लगाया ताकि भागने में कोई दिक्कत न आए। उसके बाद इन लोगो ने घटनास्थल पर दिलीप ने घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले शारदाबाई जो अपने घर मे बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी उसके सिर में गोली मारी, गोली की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में लडकी दिव्या उठी और जैसे इस तरफभागी तुरन्त उसको भी चेहरे पर आख के नीचे गोली मार दी इन दोनो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। फिर इन तीनो ने मिलकर इनके केश, ज्वेलरी आदि को लूटा और इसके बाद ये जैसे ही बाहर निकलने लगे तब तक गोविंद सोलकी जो सैलून पर काम करते है, रात्रि लगभग 9 बजे अपने घर पर पहुंचे जैसे गोविंद ने सीढियों पर चढना शुरू किया इन लोगों ने देख लिया इन लोगो ने इंतजार किया व जैसे ही गोविंद घर में घुसा घर में छिपकर गोविन्द के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी और स्कुटी की चाबी लेकर स्कुटी से फरार हो गए, बाद में एक नियत स्थान पर मिले जहां इन लोगों ने लूटी हुई सम्पत्ति का बटवारा किया और चारो फिर अपने अपने स्थानो के लिए रवाना हो गए।

किराए के मकान ले कर खोजता था शिकार दिलीप, अकेली महिलाओं को मानता था सॉफ्ट टारगेट

मामले की विवेचना और पूछताछ में पुलिस अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का मास्टर माईन्ड दिलीप देवल है जो कि, मूलतः दाहोद का रहने वाला है और पिछले लगभग डेढ़ साल से रतलाम में किराए के मकान में रह रहा है। इसने सेंटदीप की संचालिका विशाला सोलंकी के माध्यम से क्योकि दिलीप विशाला सॉलकी का पहले छात्र रह चुका है, रतलाम में अपनी पहचान बताकर किराए का मकान लेता है उसके बाद ये महिला के ही माध्यम से विभिन्न लोगो से इसकी जान पहचान होती है, लेकिन यह उस जान पहचान का फायदा उठाकर ही यह लोगो की पहचान कर कौन सा ऐसा परिवार है जहां आराम से लूट की घटना की जा सकती है, सम्पत्ति ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। साथ ही साथ जहां महिलाए ही हो ताकि उनको ज्यादा प्रतिरोध का सामना नही करना पडे, जहां पर कोई घटना के बाद शिकायतकर्ता या बताने वाला कोई न मिले, ताकि घटना का मुख्य कारण बताने वाला कोई न हो एवं पुलिस को कोई साक्ष्य न मिले।

लॉकडाउन में घर जा कर दाड़ी कटिंग बनाता था आरोपी, घर की पूरी जानकारी जुटा ली

इस तारतम्य में इसने गोविंद सोलकी से भी सम्पर्क किया जो कटिंग का कार्य करते है यह इनके यहा सेविग बनाने जाया करता था ओर लॉकडाउन के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ कि यह गोविंद सोलंकी के घर जाकर सेविग बनवाता था। उसके घर आने-जाने के दौरान ही गोविंद के घर की गतिविधियों को समझ लिया, घर की परिस्थितियो की घर की सम्पत्ति आदि चीजो को देख लिया उसके बाद से दिमाग मे इस घटना को अंजाम देना को सोचा व इसके साथी बॉबी उर्फअनुराग, गोलू उर्फ गौरव व लाला भाबोर से सांझा कर रखा था। 25 नवंबर को घटना करने के पहले ही उसने अपना किराए का मकान 23 नवंबर को खाली कर दिया था। मकान खाली कर अज्ञात जगह पर परिवार शिफ्ट कर दिया और इन लोगो के माध्यम से घटना को अंजाम दिया। अभी तक पुलिस ने इसके साथ तीन लोग जो घटना में शामिल थे गिरफ्तार कर लिया है। दो दाहोद से व एक को रतलाम से ही गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान प्रयुक्त व लूटी गई सामग्री में से काफी सामग्री को जप्त कर लिया है। लेकिन घटना का मुख्य मास्टर माईन्ड दिलीप देवल अभी भी फरार है।

जून में हुए अनसुलझे हत्याकांड का भी हुआ खुलासा

थाना औ.क्षेत्र रतलाम की ही एक और घटना जो 18 जुंन की घटना है, इसमें मृतिका प्रेमकुंवर की सिर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी उनके घर पर उनका कोई परिजन नही था। पुलिस ने हत्या का मामला पंजीबद्ध किया था वह मामला भी अभी तक अनट्रेस था। चूंकि तरीका वारदात दोनो ही घटनाक्रम मे समान था इसलिए पुलिस को पहले दिन से ही इस बात की शंका थी हो न हो इन दोनों घटना में शामिल गिरोह एक ही होगा। इस बात पर विवेचना शुरू की गई तो यह तथ्य सामने आए कि, इस घटना को भी आरोपी दिलीप देवल ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। वहां भी उक्त महिला से भी आरोपी दिलीप देवल का स्कूल संचालिका विशाला के माध्यम से ही सम्पर्क हुआ था। जब महिला ने जून में अपना स्कूल बेचा था उस दौरान मृतिका प्रेमकुंवरबाई जो कि, इस महिला को काफी पहले से 15 साल से जानती थी उसने फोन कर बताया कि, आप चाहे तो मेरे घर मे नीचे चार कमरे खाली है। जहां पर कोई माइको फायनेंस में काम करने वाला रहता था जो खाली करके चला गया है। आप चाहे तो वहां आकर किराए से रह सकती है। उक्त बात विशाला ने अपने भाई व दिलीप जिसे वह अपने बेटे की तरह मानती थी बताया। यह जानकारी मिलने पर दिलीप देवल खुद प्रेमकुवरयाई के घर गया व मकान देखने के बहाने घर की रैकी की व महिला से मिल बातचीत की व समझ गया कि महिला के पास पर्याप्त पैसा व ज्वैलरी है। मामले अन्य साथी जो इस घटना से अलग है। इसमे सुमित व हेमन्त जो कि रिश्ते में दिलीप के बड़े पापा का लडका ही है। उसके साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।

पुलिस ने किया चार को गिरफ्तार, साइको किलर है मुख्य आरोपी दिलीप देवल

उक्त घटना में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनो घटनाक्रम का मास्टर माइंड दिलीप देवल जो एक तरह का साइको किलर है जो कि लूट की घटना की नियत से घर में घुसता है व गोली मार कर हत्या करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वह कोई साक्ष्य या गवाह नही छोडना चाहता है। इस कारण अधिकतर महिला व ऐसे घर को चिहिन्त करता है जहां कोई प्रतिरोध न कर सके व इसके खिलाफकोई साक्ष्य न मिल पाये। मुख्य आरोपी अभी तक ज्ञात तथ्यो मे दिलीप देवल ने कुल 6 हत्याओं को अंजाम दिया है। दो हत्या इसने दाहोद मे एवं 4 हत्याए रतलाम में की है। दिलीप बहुत कुख्यात व शातिर साइको किलर बदमाश है। पिछले एक सप्ताह से रतलाम पुलिस के लगभग 100 से अधिक पुलिस अधिकारी लगे है, लेकिन यह अब तक लगातार अपनी लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा है। इसके गिरफ्तार के लिये पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर रखा है, जल्द ही इसे गिरफ्तार किया जाएगा।

बगैर मास्क लगाकर घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई

निःशुल्क मास्क का किया वितरण

माही की गूंज, अलीराजपुर। कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षात्मक उपाय अमजन अपनाए इसके लिए जागरूकता के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे है। साथ ही लापरवाही करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। राजस्व एवं पुलिस द्वारा अलीराजपुर में आमजन को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। राजस्व अमले ने बगैर मास्क लगाए घूमने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए निःशुल्क मास्क का वितरण किया तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क लगाने सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करने, साबुन तथा सेनेटाइजर से थोडे-थोडे समय में हाथों की सफाई करने की बात भी समझाई ।

ईवीएम मशीन से वोट डालने की दी समझाईश

माही की गूंज, मेघनगर। नगर परिषद सीएमओ निलेश डावर ने जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार आम नागरिकों एवं ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन द्वारा वोट डालने की समझाइश दी गई। आने वाले समय में हर वार्डों में जा-जाकर आम नागरिकों से किस प्रकार से वोट डालना है यह जानकारी दी जाएगी। नगर परिषद के सभी कर्मचारी जाकर वोट डालने की समझाई दे रहे हैं एवं आगामी समय में होने वाले नगरीय मतदान में लोगों को बताया जा रहा है कि, ईवीएम मशीन के द्वारा किस प्रकार व किस तरह से वोट डालना है, वार्डों में जाकर आम जनता को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

63 हजार 605 हितग्राहियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देशानुसार जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सोमवार को जिले में 1 हजार 316 हितग्राहियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। झाबुआ विकास खण्ड में 826, रणापुर में 805, रामा में 1395, पेटलावद में 1475, मेघनगर में 1686 तथा थांदला विकास खण्ड में 1316 हितग्राहियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसी प्रकार जिले में सोमवार तक 63 हजार 605 हितग्राहियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। झाबुआ विकास खण्ड में 6 हजार 851, रामा में 5 हजार 379, रणापुर में 5 हजार 122, मेघनगर में 19 हजार 419, पेटलावद में 13 हजार 962 तथा थांदला विकास खण्ड में 12 हजार 797 हितग्राहियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद ने नियमो को ताक में रख होस्टल अधिक्षक सीता ठाकुर द्वारा बिना जानकारी के तैयार आवेदन किए अग्रेषित

मूल संस्था से भेजे ही नहीं गए आवेदन तो कैसे हुई नियुक्ति

केवल प्राचार्य के अग्रेषित आवेदन को आधार बनाकर दिया जांच टीम ने गोलमोल निष्कर्ष

माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा

आदिवासी विकास विभाग झाबुआ के अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर पेटलावद में प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद, होस्टल अधीक्षक सीता ठाकुर और बाबू रामचन्द्र अटकान की मिली भगत और जिला व संभाग स्तर के बड़े अधिकारियों के द्वारा नियम विरुद्ध बाबू अटकान के परिवार की हुई थोक बन्द फर्जी नियुक्ति मामले की जांच भी भर्ती की तरह फर्जी रूप से की गई। उक्त फर्जी जांच में सभी पक्षो के बयान के बाद दर्ज प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद द्वारा नियुक्तियो के संबंध में दी गई जानकारी के बाद पूरा मामला पानी की तरह साफ्फा, जांच दल को अपने निष्कर्ष में नियुक्तियों के संबंध में जो तथ्य दिया वो स्वतः सिद्ध कर रहे है कि, जांच केवल और केवल फर्जी नियुक्ती व फर्जी नियुक्ती करने वालो व उच्च एवं जवाबदार अधिकारियों को बचाने के लिए गोलमोल जांच कर सभी को संतुष्ट करने और जांच के दायरे में आए अधिकारियों को खुश करने के लिए नाम मात्र के लिए दिखावे के लिए ही जांच के नाम पर ढकोसला मात्र किया गया।

मूल संस्था से नही भेजे गए आवेदन, एमएमडीसी की बैठक में भी नही आए आवेदन, जावक क्रमांक भी मूल संस्था का नही

वर्ष 2017 में जारी आदेश के तहत तो वेसे जिला या संभागीय स्तर के अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का कोई अधिकार नही है, जिसके चलते जो नियुक्ति 2017 के बाद सहायक आयुक्त ओर संभागीय उपायुक्त द्वारा की गई वो बिना किसी जांच के ही अवैध मानी जानी थी, लेकिन इस मुख्य तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर नियुक्तियो की जांच की गई, खेर जिस तरीके के नियुक्तियां हुई यदि उसी में हुई लापरवाही या कहे खुली सेटिंग को देखा जाए तो भी सभी भर्तियां फर्जी ही है।

प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद के बयान पर खड़े होते सवाल?

1- आवेदन नियमानुसार कन्या शिक्षा परिसर की शाला विकास प्रबंधन समिति करना था?

बयान- कन्या शिक्षा परिसर की शाला विकास प्रबंधन समिति द्वारा किसी का आवेदन प्राप्त नही हुआ।

2- आवेदन नियमानुसार मूल संस्था के जावक से जाता है?

बयान- जावक क्रमांक कन्या शिक्षा परिसर की शाला पेटलावद का नही।

3- छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रस्ताव, छात्रावास की पीटीए बैठक में प्रस्ताव, जावक भी छात्रावास अधीक्षक द्वारा

बयान - प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद के अनुसार भर्ती हेतु सम्पूर्ण कार्रवाई छात्रावास अधीक्षक सीता ठाकुर द्वारा की गई जो कि नियम विरुद्ध होकर बिना मूल संस्था के प्राचार्य की देख-रेख ओर जानकारी के होस्टल अधीक्षक को कोई अधिकार नही है।

4- आवेदन मांगने संबंधी जानकारी नही?

बयान- प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद आवेदन संबधी कोई जानकारी नही होना और छात्रावास की पीटीए बैठक की प्रोसिडिंग पर प्राचार्य के कोई हस्ताक्षर नही होना, मामले में एक नही कई होस्टल अधीक्षकों से बात की, सभी ने कहा होस्टल अधीक्षक को इस प्रकार का कोई अधिकार नही है, बिना प्राचार्य के हस्ताक्षर के ओर बिना मूल संस्था के जावक क्रमांक के किसी प्रकार का पत्र व्यवहार वैध नही है।

5- संभागीय उपायुक्त के पत्र व्यवहार की जानकारी किसको?

बयान- प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद के अनुसार तत्कालीन होस्टल अधीक्षक ने आवेदन एक दिन में भिजवाने के लिए संभागीय उपायुक्त का हवाला दिया, जबकि नियमानुसार संभागीय स्तर से किसी प्रकार की आवेदन की मांग नही हुई, यदि हुई भी है तो पत्र सहायक आयुक्त झाबुआ, जहा संबधित संस्था को जाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ, आवेदन देकर छात्रावास से ही जावक करके उसी दिन आवेदन अग्रेषित करवाए गए, नियमानुसार कोई भी प्रकिया यदि मूल संस्था के माध्यम से नही हुई तो, आवेदन अग्रेषित किए गए जबकि आवेदन प्राचार्य को अग्रेषित करना थे लेकिन प्राचार्य ने कहा आवेदन अग्रेषित करवाए गए।

जांच दल का निष्कर्ष और भी चोकाने वाला

जांच दल में शामिल नरेन्द्र भिड़े सहायक संचालक आदिवासी विकास विभाग झाबुआ जो कि पूर्व सहायक आयुक्त जमना भिड़े के पति है और जीएस चित्तोडिया सहायक ग्रेट-2 आदिवासी विकास विभाग झाबुआ द्वारा पूरी जांच के बाद अपना निष्कर्ष दिया जिसमें स्वीकार किया गया कि, जांच के दायरे में आई सभी नियुक्तिया बाबू रामचंद्र अटकान के करीबी रिश्तेदार है फिर बाबू को जांच दायरे से मुक्त करते हुए रिश्तेदारो के कथनों के आधार पर दर्शित कर्मचारियों की नोकरी नही लगवाई जाना बताया गया, साथ ही प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद के बयान के हुए मुख्य खुलासे को ताक में रख निष्कर्ष बताया कि, कर्मचारियों के दिए कथन की आवेदन कन्या शिक्षा परिसर पेटलावद के प्राचार्य को उपलब्ध कराए और आवेदन प्राचार्य द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि, आवेदन संभागीय उपायुक्त को अग्रेषित किए को आधार बनाकर जांच में सभी को पाक-साफ्फोषित कर दिया।

ये बड़े सवाल होते है खड़े

1- आखिर कैसे विभाग के एक ही बाबू के रिश्तेदार की नियुक्तिया उसी के विभाग में हुई ?

2- निष्कर्ष में जांच दल ने कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के 9 मई 2017 को जारी आदेश का हवाला नही दिया क्यो ?

3- भर्ती हुए कर्मचारियों ने कथन में आवेदन प्राचार्य को देना बताया जबकि प्राचार्य ने किसी के आवेदन की जानकारी नही होना बताया फिर कैसे कर्मचारियों की बात मानी गई, आखिर कर्मचारियों और प्राचार्य में से कौन झूठ बोला ?

4- प्राचार्य के कथन में दी गई सभी जानकारी को ताक में रखकर केवल आवेदन अग्रेषित करने को ही आधार क्यो बनाया गया ?

5- होस्टल अधीक्षिका सीता ठाकुर के बयान क्यो दर्ज नही किए गए ?

6- होस्टल अधीक्षिका से संभागीय उपायुक्त ने आवेदन एक दिन में किस पत्र के माध्यम से सीधे मंगवाए थे, कोई लिखित प्रमाण क्यो नही लिया गया ?

सवाल और भी खड़े होते है, सवाल अधिकारियो पर ओर सवाल जांच दल पर भी खड़े होते है कि, आइने की तरह साफ फर्जी नियुक्ति घोटाले पर आखिर किसके इशारों पर पर्दा डाला गया, जांच के दायरे में फर्जी वेतन भुगतान को क्यो शामिल नही किया गया, इसका निर्णय न्यायालय में जरूर होगा क्योंकि कहते है सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित नही। गूंज की पहल सिर्फ विभाग के काले कारनामे उजागर कर शासन के नियमो ओर कानून को अपने पैर की जूती समझकर माल कमाने वाली दधारू गाय समझने वालों कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को सामने लाया गया है बाकी की कार्रवाई सरकार और अधिकारियों को करनी है जो अपने ईमानदार होने के खोखले दावे कर भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम देने के दावे करते है।

गड़बड़ी की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने नही की कार्रवाई, सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत के बाद आया हरकत में

कालाबाजारी करने वाला सेल्समैन निकला भाजपा जिलाध्यक्ष का भाई

कालबाजारी को संरक्षण देने वाली गरवाड़ा और देवड़िरी की सरकारी उचित मूल्य की दुकानें सील

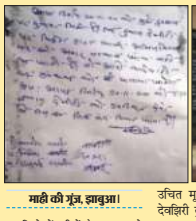

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में गरीबों के अनाज को किसी बड़े मच्छर की तरह खून चूसने वाले की तर्ज पर डाका डाला जा रहा है। जिले के बड़े अनाज माफिया के रूप में कांग्रेस की सरकार में बना रिंग मास्टर भाजपा की सरकार में बन गया सर्कस मास्टर पूर्व कांग्रिस जिलाध्यक्ष सुरेश जैन (पप्पू सेठ) सहित कई लोग जेल की हवा खा चुके है, लेकिन निचले स्तर पर कई सोसाइटियों में सेल्समैन पूरे सिस्टम को दिमक की तरह साफ कर गरीबो को मिलने वाले अनाज पर डाका मार रहे है।

मामला जिले के देवड़िरी आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत आने वाली दो सरकारी उचित मूल्य की गडवाड़ा और देवड़िरी दुकानों पर सोमवार को प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। कार्रवाई देवड़िरी सोसायटी के मैनेजर द्वारा की गई। मामले की लगातार शिकायत की जा रही थी लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद में मामला सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गया तब कही जाकर जिम्मेदारों की नींद खुली। कार्रवाई से जुड़े अधिकारी ने बताया कि, खबर मिली थी कि, दोनों जगह राशन और अनाज में कालाबाजारी हो रही है और पुख्ता प्रमाण के साथ कालाबाजारी करने हेतु दुकान के अलावा दूसरी जगह अनाज भरकर रखा गया है की जानकारी मिली। जिसपर कार्रवाई करते हुए एक मकान में हमें राशन मिला भी है, उक्त दोनों दुकानों पर सेल्समैन नगीन नायक है, दोनों दुकानों का सेल्समैन नगीन नायक भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक का भाई है।

मामले में मैनेजर ने कार्रवाई के पहले एक पत्र प्रशासक को लिखा जिसमें बताया गया कि, दोनों दुकानों में अनियमिता की शिकायत मिली है, साथ ही अनाज ऊचे दाम पर बेचने के लिए रखा है। और ये भी खबर है कि, सेल्समैन ने बैंक शाखा से अवैध तरीके से रसीद बुक ले रखी है, जिसका संस्था स्तर पर और बैंक में भी कोई रिकार्ड नहीं है और सदस्यों के नाम से लोन बढ़ाने के लिए ये किया गया। उक्त सेल्समैन नगीन नायक का नाम पूर्व में भी गबन में आ चुका है। कहीं न कहीं सेल्समैन नायक को राजनीतिक सहयोग या अधिकारीयों की मिलभगत का इनाम मिलता रहा है, जो लगातार शिकायतों के बाद भी हर बार किसी भी कार्रवाई से बचने में कामयाब रहा है। अब जब कार्रवाई हुई है तो संशय है कि, कोई आरोप सिद्ध होंगे या नही? क्योंकि सेल्समैन नायक अपने आपको बचाने के लिए धन, बल और प्रभाव की पूरी ताकत लगाएगा, वहीं कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारियों को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है।

आपरेटर को भी हो चुका है नोटिस जारी

पूर्व में पदस्थ रहे कम्प्यूटर ऑपरेटर मनीष नायक को नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस मदद योजना के 15 क्विंटल गेहूं और राशन की हेराफेरी को लेकर है। मैनेजर ने बताया, मदद योजना में किसी की मौत होने पर सरकार द्वारा परिवार के कार्यक्रम के लिए 5 क्विंटल अनाज दिया जाता है, मनीष ने 25 क्विंटल गेहूं देना बताया, लेकिन इसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, इसके अलावा एक महिला कर्मचारी ने लिखित में दिया कि, उसने संस्था के 42 हजार रुपए मनीष को दिए थे, उसने वो भी जमा नहीं किए। बारदानों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है, 31 मार्च की स्थिति में स्टॉक बता दिया, लेकिन बारदान वापस जमा कराने या उसका पैसा जमा कराने का कोई प्रोसेस या कार्य नहीं किया गया।

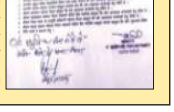

लाशों के नाम पर पैसा नोचने वाली बरवेट पंचायत

एक के बाद एक पंचायत के सभी मुक्ति धाम के पैसे डकारने वालो पर आखिर कब होगी कार्रवाई ?

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बरवेट में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, बरवेट पंचायत में एक के बाद एक मुक्तिधाम में भारी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे है, पंचयात के गांव बरवेट, जुलवानिया के बाद सूचना अधिकार में मिली जानकारी में ग्राम मोटापाला में 5 लाख 40 हजार रूपए की लागत से बनाए गए मुक्तिधाम में भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन मौके पर कार्य की गुणवत्ता और कार्य को देखकर कोई भी बता सकता है कि, ग्राम पंचायत ने एक से डेढ़ लाख का खर्च कर बाकी फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली गई। निर्माण कार्य मे लगभग 3 लाख रुपए के मटेरियल के बिल लगाए गए, जिसमे आधे बिल मुहर्रम ठुलाई के लगाए गए, कुछएजेंसी के पास वाहन नही होने के बाद भी मोहर्रम के बिल भुगतान किए गए, कालूसिंह नानूरम सोलंकी निवासी मोटापाला के नाम से 19 हजार 500 रुपए का बिल लगा हुआ है जबकि कालूसिंह का कहना है कि, उसके द्वारा कोई बिल पंचायत को नही दिया गया।

भटेवरा एग्रो एजेंसी बरवेट का भी 55 हजार 640 रुपए का मोहर्रम धुलाई का बिल का भुगतान किया गया जबकि एजेंसी के पास किसी प्रकार का ट्रेक्टर या डम्फ नही है, ग्राम बाचीखेड़ा की एजेंसी जो कि ग्राम से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है वहा की विश्वमंगल कंट्रक्शन द्वारा पानी सप्लाई दस हजार रूपए का किया गया, लगभग 20 किलोमीटर दूर हमीरगढ़ की एजेंसी राधास्वामी कंट्रक्शन द्वारा दस हजार का मोहर्रम सप्लाई का बिल लगाया गया, लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम करवड़ से श्री माँ यादें कोल ट्रेडर्स का बिल इट और पानी का 11 हजार 500 रुपए के लगभग के बिल का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य मे स्टील, चहर जीसीआई सीट के भारी मात्रा के एक लाख के अधिक के बिल का भुगतान किया गया, लेकिन मुक्तिधाम पर बमुश्किल 30 से 35 चहर ओर एंगल का सेट मात्र लगा हुआ है। सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त करने वाले शिकायतकर्ता दुर्गादास राठौर ने बताया कि, ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का भराव नहीं किया है, जिसके लिए इतना भुगतान किया जाए, मौके पर किसी भी उपयोगी से कार्य का मूल्यांकन करवाया जाए तो पता चल जाएगा कितने का कार्य हुआ है, कार्य मे फर्जी हाजरी भरकर फर्जी भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा कई बार पंचायत के भ्रष्टचार की शिकायत की मगर जिम्मेदारो ने अन्य पंचायतो की तरह यह भी जांच के नाम पर ग्रामीणों को गुमराह कर किसी प्रकार की कार्रवाई नही की और भ्रष्टाचार की नदी में खुद भी गोते लगा दिए।

रोजगार सहायक जांच के डर से हुआ रवाना

वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत बरवेट में बने मुक्तिधाम के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टचार में ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक जवरसिंह ने पंचायत में भ्रष्टाचार किए, मुक्ति धाम निर्माण में अधिकांश बिल रोजगार सहायक के माध्यम से लगे थे। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार भ्रष्टाचार की जांच के डर से खुद ही आवेदन देकर अपना स्थानन्तरण अन्य पंचयात में करवा लिया। यदि नौकरी लगने के बाद से रोजगार सहायक की सम्पत्ति की जांच की जाए तो अवैध रूप से अर्जित की अचूक सम्पत्ति का बड़ा खुलासा हो सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422